

हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग



वार्षिक योजना बजट

2016-17

के लिये माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु दिनांक 4 तथा 5 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की कार्यवाही ।

योजना विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

आवश्यक

संख्या:योजना .एफ.सी.(एफ) 3-1/2014-15-मिन्टस
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषक

सलाहकार (योजना),
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-2.

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0।
3. समस्त सम्बन्धित निगमों/बोर्डों के प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0।
4. समस्त मण्डल आयुक्त, हि0प्र0।
5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-2,

24th मई, 2016.

विषय: वार्षिक योजना बजट 2016-17 के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु दिनांक 4-2-2016 तथा 5-2-2016 को आयोजित बैठकों की कार्यवाही।

महोदय/महोदया,

मुझे माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में माननीय विधायकों के साथ वार्षिक योजना 2016-17 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारण करने हेतु दिनांक 4-2-2016 तथा 5-2-2016 को आयोजित बैठकों की कार्यवाही का विवरण संलग्न करने का निर्देश हुआ है। आपसे यह अनुरोध है कि माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए निर्देशों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कृत कार्यवाही से मुख्य मन्त्री कार्यालय, सभी सम्बन्धित माननीय विधायकों तथा योजना विभाग को सूचित करने की अनुकम्पा करें।

सम्बन्धित विभाग बैठकों की कार्यवाही का विवरण योजना विभाग की वेबसाइट hpplanning.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया उपरोक्त वर्णित बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी केवल हिन्दी भाषा में विभागीय ईमेल hp_planninh@yahoo.com के माध्यम से अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृपया मामले को उच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:-

दिनांक, शिमला -2 24th मई, 2016.

1. समस्त माननीय विधायक, हिमाचल प्रदेश।
2. निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, माननीय ----- मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0 शिमला-2.
5. समस्त प्रभागाध्यक्ष, योजना विभाग हि0प्र0, शिमला-2. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)

विषय सूची

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पृष्ठ
1.	2.	3.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वागत भाषण का संक्षिप्त विवरण ।		1-1
1. जिला सोलन		
1.	सोलन	2-2
2.	अर्की	2-3
3.	कसौली	3-4
2. जिला सिरमौर		
1.	पच्छाद	4-5
2.	नाहन	5-6
3.	शिलाई	6-7
3. जिला शिमला		
1.	चौपाल	8-9
2.	कसुम्पटी	9-10
3.	शिमला	10-11
4.	जुब्बल-कोटखाई	11-12
5.	रोहडू	12-13
4. जिला मण्डी		
1.	सेराज	13-13
2.	धर्मपुर	14-14
3.	सरकाघाट	15-15
5. जिला कुल्लू		
1.	मनाली	16-16
2.	आनी	16-17

6. जिला बिलासपुर		
1.	बिलासपुर	17-17
2.	श्री नैनादेवी जी	17-18
7. जिला काँगड़ा		
1.	इन्दौरा	18-18
2.	ज्वालामुखी	18-19
3.	ज्वाली	19-19
4.	जयसिंहपुर	20-21
5.	सुलह	21-21
6.	बैजनाथ	21-22
8. जिला लाहौल-स्पीति		
1.	लाहौल स्पीति	23-24
9. किन्नौर		
1.	किन्नौर	24-24
10. जिला चम्बा		
1.	चुराह	24-25
2.	डलहौजी	25-26
	भटियात	26-28
11. जिला ऊना		
1.	गगरेट	28-29
12. जिला हमीरपुर		
1.	भोरंज	29-29
2.	सुजानपुर	30-30
3.	बड़सर	30-31
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश ।		32-34
अनुबन्ध “क” - माननीय मुख्य मन्त्री का उद्घाटन भाषण ।		35-37
दो दिवसीय बैठकों की जिलावार समय सारणी।		38-38
जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार बैठकों में भाग लेने वाले माननीय मन्त्री / मुख्य संसदीय सचिवों एवं विधायकों का ब्यौरा ।		39-40

वार्षिक योजना 2016-17 की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 2016 को श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों की कार्यवाही ।

सर्वप्रथम डॉ० श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने माननीय मुख्य मंत्री, मन्त्रियों, उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड), उपाध्यक्ष (हि०प्र० विधान सभा), संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा समस्त उपस्थित अधिकारियों का दो दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए स्वागत किया। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री का व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद दो दिवसीय बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए आभार प्रकट किया तथा स्पष्ट किया कि माननीय विधायकों के साथ विचार-विमर्श के लिए निर्धारित बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं । क्योंकि इन बैठकों में विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अतिरिक्त मितव्ययता, वित्तीय संसाधन जुटाने, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व wage employment सृजित करने के लिए भी बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं जोकि राज्य के बजट तैयार करने तथा प्रदेश के सन्तुलित एवं तीव्र विकास के लिए कारगर होते हैं । अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने आग्रह किया कि सम्बन्धित implementing विभाग योजनाओं की DPRs की स्थिति, योजना स्वीकृति एवं योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की जानकारी समय-समय पर सम्बन्धित माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाएंगे ताकि माननीय विधायकों के अनुभवों का लाभ स्थानीय स्तर की समस्याओं को दूर करने में किया जा सके जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन को गति मिल सके । माननीय विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों तथा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है । सभी विधायकों की प्राथमिकताओं की योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्राप्त मार्गदर्शन तथा इन बैठकों से मिलने वाले Feedback के आधार पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने माननीय मुख्य मंत्री से सम्बोधन करने एवं मार्गदर्शन देने का आग्रह किया ।

माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने उद्घाटन भाषण (अनुबन्ध-“क”) के उपरान्त चुनाव क्षेत्रवार बैठक का शुभारम्भ किया । जिला एवं चुनाव क्षेत्रवार दो दिवसीय बैठकों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों एवं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दो दिवसीय बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	जिला / माननीय विधायक / निर्वाचन क्षेत्र / बैठक में उठाये गए मुद्दे	सम्बन्धित विभाग
1.	2.	3.
1. जिला सोलन		
1. श्री धनीराम शांडिल, सोलन		
1.	जंगली जानवरों की बढ़ती हुई समस्या को रोकने हेतु Solar Power Fencing योजना आरम्भ की जाए ताकि फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके जिससे कृषि एवं बागवानी सुरक्षित रहे। यह बहुत महंगी योजना भी नहीं है व इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे।	कृषि/ पशुपालन विभाग
2. श्री गोबिन्द राम शर्मा, अर्की		
1.	पिछले वर्ष की विधायक प्राथमिकता की सभी उठाऊ सिंचाई योजना जैसे बुघार, मटेरनी, मलौण, भूमति, इत्यादि में नॉट फिज़ीबल लिखा है। मटेरनी तथा बलेरा पंचायत क्षेत्र में डैम बन जाए तो वहां सिंचाई योजना बन सकती है। इस बारे में विभाग दोबारा सर्वे करे ताकि सिंचाई योजना बन जाए। रोहान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और बरसात के पानी को इकट्ठा करके वहां टैंक बनाया जाए तो क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो सकेगी।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	अर्की विधान सभा क्षेत्र में दो बहुत बड़े सीमेंट उद्योग जे०पी० व अम्बूजा के हैं, वहां पर ट्रकों और भारी वाहनों की काफी आवाजाही रहती है। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बन सकता है जिसकी घोषणा की जा चुकी है परन्तु अभी तक फॉरैस्ट केस व भूमि स्थानान्तरण नहीं हुआ।	परिवहन/वन/ राजस्व विभाग
3.	लो०नि०वि० में अति-आवश्यक सड़कों की डी०पी०आर० नहीं बनाई गई। जैसे कि सड़क पंजली से चंधार तक, मटेरनी, मलौण तथा बलेरा से अर्की तक। विभाग सर्वे करें ताकि लोगों को सुविधा हो। क्षेत्र में	लो०नि०/वन विभाग

	बहुत से रोड फॉरेस्ट केस के कारण रुके पड़े हैं जैसे जघून-जैनख, सैंज से बाड़ीधार तथा मज्याट-पपलोटा-डुमैहर सड़कें। जिन सड़कों के फॉरेस्ट केस नहीं हो पाए हैं उनकी joint inspection के लिए लो०नि० व वन विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए ताकि स्कीमों को तुरन्त approval मिल सके। सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किये जायें।	
4.	FRU अर्की में स्वीकृत किया गया है परन्तु वहां डाक्टर नहीं है। डाक्टर को फील्ड से depute किया जाता है जिससे फील्ड में भी समस्या आती है। जैसे पी०एच०सी० बलेरा, डुमैहर, भूमति तथा धुन्धन इत्यादि में भी डॉक्टरों व पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी है। जिसे दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए। जहां अध्यापक की आवश्यकता है उसके लिए प्रावधान किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत न आए। सीनियर सैंकेडरी स्कूल बुघार तथा लोहारघाट में भवनों का निर्माण किया जाए।	उच्च/ प्रारम्भिक शिक्षा/ लो०नि० विभाग
6.	नेरी-प्लाटा, ग्राम पंचायत दानोघाट और दूसरी पेयजल योजना सनोग, बड़ोलू, बड़ोग, ब्राह्मणा, सयोल, जीना फांगी, चांगर, नवोग तथा पनसेटा ग्राम पंचायत बड़ोग का शिलान्यास चार साल पहले हुआ था। ग्राम पंचायत दानोघाट का 20 प्रतिशत कार्य भी नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत बड़ोग का कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ। इनका कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। अति आवश्यक सिंचाई योजनाएं या पेयजल योजनाओं का कार्य शीघ्र होना चाहिए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
7.	घड़याच स्कूल में बच्चों को 25 कि०मी० की दूरी से आना पड़ता है। लगड़ाघाट स्कूल में भी बच्चे बहुत दूर से आते हैं। इन स्कूलों को स्तरोन्नत किया जाए।	उच्च/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
3. डॉ० राजीव सैजल, कसौली		
1.	वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में जितनी भी सड़कों को विधायक प्राथमिकता में दिया था उनमें एक भी सड़क की डी०पी०आर० नहीं बनाई गई। विभाग को आदेश दिए जाएं कि सड़कों की लम्बित डी०पी०आर० प्राथमिकता पर तैयार की जाएं।	लो०नि० विभाग
2.	कसौली निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। कुछेक ट्रेकिंग रूट्स ब्रिटिश काल से हैं उन्हें पुर्नजीवित किया जाए जैसे परवाणू-कालका-कसौली रूट, इत्यादि।	पर्यटन विभाग/ वन विभाग
3.	गम्भरपुल बहुत पुराना व तंग है। अतः उसे नया चौड़ा पुल निर्मित किया जाए। सड़कों की मुरम्मत नहीं हो रही है जैसे कि धर्मपुर से कसौली सड़क, धर्मपुर-सपादू वाया कंडा सड़क की हालत बहुत खराब है। इन सड़कों की मुरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।	लो०नि० विभाग

4.	प्रदेश के महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की दिशा में समय रहते सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं जिससे पर्यटन प्रभावित न हो।	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. जिला सिरमौर		
1. श्री सुरेश कुमार, पच्छद		
1.	विधायक प्राथमिकता की स्कीमों के शिलान्यास पर सम्बन्धित विधायक को भी बुलाया जाए। तथा लम्बित डी0पी0आर0 को शीघ्र बनाया जाए।	लो0नि0वि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	पच्छद चुनाव क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में जे0ई0 की भारी कमी है खाली पद भरे जाएं व सड़कों की शीघ्रातिशीघ्र फॉरैस्ट क्लीयरेंस करवाई जाए।	लो0नि0/ वन विभाग
3.	राजगढ़-चंदोल सड़क की डी0पी0आर0 नहीं बनी। इसे चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है, इसकी डी0पी0आर0 शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाए। सोलन-मीनस सड़क को Inter-State-Connectivity में बनाया जाए क्योंकि यह प्रदेश को उतराखण्ड से जोड़ती है। इस सड़क की Tarring उखड़ गई है, जिसे ठीक किया जाए। सराहां-चण्डीगढ़ सड़क की हालत बहुत खराब है जिसमें सुधार किया जाए। यह सड़क भी हिमाचल प्रदेश को चण्डीगढ़ और हरियाणा से जोड़ती है, इस सड़क को भी Inter-State-Connectivity में बनाया जाए। छैला-नेरीपुल-ओछघाट सड़क तीन जिलों को जोड़ती है तथा सेब सीजन में सारे सेब की ढुलाई इस सड़क से होती है। इस सड़क का सुधार किया जाए तथा इसकी डी0पी0आर0 शीघ्र बनाई जाए। PMGSY के अन्तर्गत सड़कों में जहां लोगों की निजी भूमि शामिल है उस पर लोगों ने KCC बनाई हुई है, वहां पर दिक्कत आ रही है। इसके लिए लोगों से affidavit या NOC लिये जाएं और इन सड़कों का निर्माण किया जाए।	लो0नि0 विभाग
4.	आई0पी0एच0 विभाग में स्टाफ की कमी है। सराहां व राजगढ़ sub-division में जे0ई0 के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
5.	पच्छद विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की जितनी भी स्कीमें हैं उनमें फिल्टर की कोई सुविधा नहीं है। जहां फिल्टर नहीं है वहां फिल्टर का निर्माण किया जाए और चॉक हुए फिल्टरस को ठीक किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	विकेन्द्रीकृत मद की स्कीमों को पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। इसके लिए एक मुश्त में बजट का प्रावधान किया जाए।	योजना विभाग (R&DP Division)
7.	पिछले वर्ष पच्छद विधान सभा क्षेत्र में 100 हैंडपम्पों की डी0पी0आर0	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

	बनवाने के लिए विधायक प्राथमिकता में डाला गया था जिसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। अतः इनकी डी०पी०आर०सी० शीघ्र बनवाई जाएं।	
8.	पांच पी०एच०सी० चलोह, डिम्बर, कोटी पधोग, धामला तथा बागथन में पिछले तीन वर्ष से डॉक्टर नहीं है। सीविल अस्पताल सरांह में एक डाक्टर का पद खाली है तथा सी०एच०सी० नारग में भी एक डॉक्टर की कमी है। अतः डाक्टरों के पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए तथा पैरा मैडीकल स्टाफ व फार्मासिस्ट की भी भर्ती की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	पिछले 11 वर्ष से निर्माणाधीन राजगढ़ कॉलेज का निर्माण कार्य तथा सराहां कॉलेज जिसके भवन का शिलान्यास हो चुका है, के भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा एवं शुरू करवाया जाए। सरांह व राजगढ़ आई०टी०आई० के भवन निर्माण कार्य शीघ्र किए जाएं।	उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा/लो० नि० विभाग
10.	स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है पिछले दिनों कुछ अध्यापकों के पद SMC के माध्यम से भरे गए थे लेकिन अभी भी अध्यापकों की कमी है। इसको देखते हुए या तो अध्यापकों के रिक्त पदों को SMC के माध्यम से या नए पद भर्ती नियम के माध्यम से शीघ्र भरे जाएं।	उच्च/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
11.	ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या अन्य कोई भी कार्य जो एस०डी०एम० कार्यालय से होने होते हैं उसके लिए राजगढ़ जाना पड़ता है। अतः सरांह में एस०डी०एम० कार्यालय खोला जाए। और जब तक एस०डी०एम० कार्यालय सरांह में न खुले तब तक महीने में 15 दिन एस०डी०एम० सरांह में बैठे और 15 दिन राजगढ़ में बैठने की व्यवस्था की जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
12.	पर्यटन की दृष्टि से पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार सम्भावना है। कांगड़ा के बिलिंग की तरह सेरजगास में भी पैराग्लाइडिंग की सम्भावना है। अगर वहां पर भी लगातार पैराग्लाइडिंग होता रहे तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।	पर्यटन/ विभाग/ Mountaineering & Allied Sports
13.	दुर्घटना के मामले में प्रदान की जाने वाली त्वरत राहत धनराशि बहुत कम है। तहसीलदार के पास ऐसा फंड होना चाहिए जिसे casualty accidental case को immediate relief के आधार पर दिया जा सके।	राजस्व विभाग
14.	विधायक निधि की राशि को 75 लाख रु० से बढ़ाकर डेढ़-दो करोड़ रु० तक किया जाए।	योजना विभाग (R&DP Divn.)
2. डॉ० राजीव बिन्दल, नाहन		
1.	चुनाव क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाए।	पर्यटन विभाग
2.	प्रदेश में सूखे की स्थिति गम्भीर हो गई है इसका आंकलन करें व किसानों को राहत के लिए कोई योजना बनाई जाए।	राजस्व/कृषि विभाग
3.	सुकेती सड़क की स्थिति बहुत खराब है। यह दो राज्यों को आपस में	लो०नि० विभाग

	जोड़ती है। इसको सी०आर०एफ० या Inter-State Connectivity में बनाया जाए।	
4.	पिछले साल की विधायक प्राथमिकता में दिए गए हैंडपम्प की डी०पी०आर० पर विभाग द्वारा जो query लगाई गई है, वह तर्कहीन है, उसे विभाग द्वारा हटाया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
5.	जो सड़के पंचायती राज तथा लो०नि०वि० द्वारा बनाई जाती हैं उनके रख-रखाव के लिए धनराशि बहुत कम होने के कारण इन सड़कों की maintenance सही ढंग से नहीं हो पा रही है।	लो०नि० एवं पंचायती राज विभाग
6.	आई०पी०एच० की 70 प्रतिशत योजनाओं के पम्प व मोटर खराब हैं उनकी रिपेयर और maintenance के लिए बजट का प्रावधान किया जाए और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत दो पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पाईपों को बदलने के लिए स्वीकृत धनराशि विभाग को दी जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
7.	विधायकों की recommendation पर DCP फण्ड से योजनाएं स्वीकृत की जायें। मुख्यमंत्री द्वारा की गई स्कीमों की घोषणाओं के लिए पैसा नाबार्ड या केन्द्र प्रायोजित अन्य स्कीमों से दिया जाए न कि डी०सी०पी० से जैसे कि पेयजल योजना पलोड़ी को डी०सी०पी० से 35 लाख रु० दिया गया जबकि ऐसी स्कीमों की फंडिंग किसी अन्य Head के अन्तर्गत की जा सकती है।	योजना विभाग (R&DP Divn.)/उपायुक्त सिरमौर
8.	16 सड़कों की डी०पी०आर० इसलिए लम्बित हैं क्योंकि वन, लो०नि० व राजस्व विभागों की joint meeting नहीं होती। इस सम्बन्ध में उचित निर्देश दिए जाएं।	लो०नि०/ वन राजस्व विभाग/ उपायुक्त सिरमौर
9.	PHCs के भवन निर्माण के लिए कुछ पैसा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को दिया गया उसे विभाग ने दूसरे स्थान पर लगा दिया। उस पैसे को PHCs और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को वापिस दिया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10.	जंगली जानवरों द्वारा खेती को होने वाले नुकसान के समाधान के सम्बन्ध में गम्भीर नीति बनाने की जरूरत है।	पशुपालन/वन/वन्य प्राणी/ कृषि/ बागवानी विभाग
11.	बढ़ती बेरोजगारी बारे गम्भीरता से विचार किया जाए। उद्योगों में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने बारे उद्योग गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं इस बारे विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करें।	श्रम एवं रोजगार/ उद्योग विभाग
3. श्री बलदेव सिंह तोमर, शिलाई		
1.	NH 72-B लालढांग से रोहडू तीन निर्वाचन क्षेत्रों से होकर जाती है, के दूसरे भाग के टैन्डर जल्दी से शुरू किए जाएं। इस सड़क की हालत बहुत खराब है।	लो०नि० विभाग

2.	पिछले तीन वर्षों में दी गई विधायक प्राथमिकता योजनाओं की कोई भी डी0पी0आर0 नहीं बन पाई है।	लो0नि0वि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
3.	बहुत सी सड़कें/सम्पर्क सड़कें बन कर तैयार हैं परन्तु विभाग द्वारा अभी तक इन सड़कों को बस चलाने योग्य पास नहीं किया है। इन्हें शीघ्र पास करवाकर बसें चलाई जाएं। पंचायत से बनी सड़कों के रख-रखाव के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	HRTC/ लो0नि0 विभाग
4.	पीने के पानी की बहुत समस्या है। 18 स्कीमों पर पिछले 7-8 वर्ष से काम चला हुआ है परन्तु HPSEBL SOP नहीं दे पा रहा है। उनके पास High voltage connector नहीं है।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/HPSEBL
5.	आई0पी0एच0 डिवीजन पांवटा साहिब के अनतर्गत रोन्हाट उपमण्डल बनाया जाए। विधान सभा क्षेत्र शिलाई में अलग से एक आई0पी0एच0 डिवीजन बनाया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	जो बी0डी0ओ0 स्थानान्तरित किए गए हैं उनका स्थानान्तरण cancel किया जाए। 7-8 पी0एच0सी0 में एक भी डाक्टर नहीं है।	ग्रामीण विकास/ पंचायती राज/ स्वास्थ्य विभाग/ समस्त विभाग
7.	रोन्हाट में कॉलेज खोला जाए। शिक्षा विभाग में खाली पद भरे जायें।	शिक्षा विभाग
8.	आई0टी0आई0 शिलाई व कफोटा का 2012 में शिलान्यास हुआ था, आज तक भवन नहीं बन रहा है जिसका जल्द ही टैन्डर लगाया जाए।	लो0नि0/ तकनीकी शिक्षा विभाग
9.	पांवटा साहिब में बसों की कमी को देखते हुए पाँवटा में HRTC का एक सरकारी बस डिप्टो खोला जाये। एच0आर0टी0सी0 की एक भी बस रात को नहीं रुकती है।	HRTC
10.	वॉल्वो बस पांवटा से दिल्ली को बंद की गई है, उसे कम से कम छः महीने तक ट्रायल पर रखें ताकि लोगों को सुविधा हो।	HRTC
11.	फॉरेस्ट क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है इस पर चैक लगाया जाए।	वन/खनन विभाग
12.	विधायक निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है।	योजना विभाग (R&DP Div.)
13.	रेणुका के जाखना में कॉपरेटिव बैंक खोलने बारे सर्वे करवाया जाए।	IF
14.	शिलाई चुनाव क्षेत्र में सभी विभागों के रिक्त पद भरे जायें।	समस्त सम्बन्धित विभाग

3.जिला शिमला

1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल

1.	चौपाल और नेरवा अस्पताल में भवन की कमी है। शीघ्र ही अस्पताल बिल्डिंग का टैन्डर लगाया जाए। पांच पी0एच0सी0 नौहरा, वोहरा, गुम्मा, झिन्ना तथा बम्टा में निजी भूमि उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी है इसकी बिल्डिंग के लिए फण्ड का प्रावधान किया जाए। सी0एच0सी0 कुपवी के लिए फण्ड का प्रावधान किया जाए।	स्वास्थ्य/लो0नि0 विभाग
2.	पुलवाहल क्षेत्र की तीन पंचायतें जोना, पुलवाहल और सरी को सरांह से सड़क द्वारा जोड़ा जाये। कुपवी-दर्इया सड़क के लिए पैसा sanction हो गया, फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी आ गई पेड़ों की संख्या 600 की जगह 300 पेड़ लिखे गए इसलिए सड़क का कार्य रुका हुआ है। अतः फॉरेस्ट विभाग इसके लिए आगे वाले भाग का फॉरेस्ट क्लीयरेंस केस भेजे। सैंज-फेड़ज पुल सड़क बहुत नैरो है। इसे किसी प्रोजेक्ट में डालकर कम से कम चौपाल तक चौड़ा किया जाए।	लो0नि0/ वन विभाग
3.	नेरवा कॉलेज के निर्माण के लिए अतिरिक्त फण्ड जारी किये जाएं।	शिक्षा विभाग
4.	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरांह का भवन जो जल गया था, के पुर्ननिर्माण के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान शीघ्र किया जाए।	शिक्षा विभाग
5.	चौपाल में कम वोल्टेज की समस्या है तथा 25 KVA के 10 ट्रांसफार्मर जले हैं जिनकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है व 66 KVA लाश्टाधार की लाईन के कार्य में तेजी लानी होगी जिसके लिए धन का प्रावधान किया जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
6.	आई0पी0एच0 की 10 लिफ्टें निर्माणाधीन हैं। टैंक बनाने के लिए धन का प्रावधान किया जाए। चौपाल में पीने के पानी की समस्या बारे विचार किया जाए व जिन लिफ्टों का कार्य चल रहा है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
7.	H.R.T.C. डीपो नेरवा में चालकों/परिचालकों की कमी को जल्दी पूरा किया जाए। बसें जल्दी से जल्दी लगें तथा ट्रांसपोर्ट डीपो नेरवा के लिए पैसा जल्दी sanction हो जाए।	HRTC/ बस अड्डा प्राधिकरण
8.	चौपाल में पंचायती राज से बनी लगभग 600 सड़कों की renewal के लिए ऐसे फण्ड का प्रावधान किया जाए जिसे वर्षा ऋतु में सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जाए।	उपायुक्त शिमला/ ग्रामीण विकास/ लो0नि0 विभाग

9.	कुपवी में नया विकास खण्ड बनाया जाए।	ग्रामीण विकास
10.	कुपवी में आई0टी0आई0 खोली जाए।	तकनीकी शिक्षा
11.	चौपाल में कॉलेज खोला जाए।	शिक्षा विभाग
12.	बलसन क्षेत्र के देहा में पुलिस थाना खोला जाए।	गृह/पुलिस विभाग
13.	नेरवा उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए।	राजस्व विभाग
14.	विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रु0 किया जाए।	योजना विभाग (R&DP Divn.)
2. श्री अनिरुद्ध सिंह, कसुम्पटी		
1.	कुछ स्कूलों जैसे जुगर ग्राम पंचायत सतोग, दलाऊ ग्राम पंचायत चियोग, सौल ग्राम पंचायत बल्देयां, ढली स्कूल और राजकीय माध्यमिक पाठशाला भराड़िया की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी ये स्कूल notify नहीं हुए हैं। इन स्कूलों को notify किया जाए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी में साईस ब्लॉक भवन के निर्माण के लिए लगभग 15 लाख रु0 की जरूरत है, धन का प्रावधान किया जाए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरेच के लिए अतिरिक्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। इसी प्रकार कसुम्पटी स्कूल जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोट शिमला के नाम पर है, की बिल्डिंग का कार्य ठेकेदार ने लगभग पूरा कर दिया है लेकिन इसके लिए फंड allocate नहीं हुआ है। अतः इसकी कम्प्लीशन के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा/लो0 नि0 विभाग
2.	शिमला में सीवरेज की समस्या बड़ी गम्भीर है। मैहली से पंथाघाटी सीवरेज लाईन के लिए फण्ड का प्रावधान किया जाए। कैलेस्टन क्षेत्र के बिजली बोर्ड की कॉलोनी में सैप्टिक टैंक भर गया है, सीवरेज का गंदा पानी बाहर बह रहा है, इसके लिए भी धन का प्रावधान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में पाईपें बिछनी है, जैसे गांव रगैन सीवरेज लाईन में पाईपों की कमी के कारण काम नहीं हो रहा है। लम्बीधार सीवरेज लाईन में 1500 मीटर सीवरेज लाईन बिछनी है। गांव छकडैल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्ठाकुफर तथा नगर निगम क्षेत्र छोट शिमला के विजयनगर में सीवरेज लाईन बिछनी है जिसके लिए धन का प्रावधान किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ नगर निगम शिमला/ शहरी विकास विभाग
3.	विधायक प्राथमिकताओं की स्कीमों के सर्वे समयबद्ध अवधि में करवाए जाएं और उसके लिए liability fix हो।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
4.	बल्देयां से लेकर खटनोल तक जोकि मूलकोटी सड़क का हैड प्वाइंट है, कोगी-सरीऊं सड़क तथा ढली-सुन्नी सड़क की मैटलिंग उखड़ गई है और गड्ढे भी बहुत हैं। इसकी मैटलिंग का कार्य शीघ्र करवाया जाए। च्योग-ठियोग उपमण्डल की सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। कांडटी तथा लखोटी पुल की रिवाइज्ड ड्राईंग लो0नि0वि0 शीघ्र दें। कुफरी	लो0नि0 विभाग

	बाजार में interlocking tiles का कार्य शीघ्र करवाया जाए।	
5.	पी0एच0सी0 न्यू शिमला के लिए बकाया रु0 46,500/- की राशि उपलब्ध करवाने का मामला solve किया जाए। पी0एच0सी0 कनोला, धरेच, ट्राई में फारेस्ट कलियरेंस केस शीघ्र तैयार करके कार्य शुरू किया जाए। चम्याणा (दूसरे चरण) तथा भट्ठाकुफर अस्पताल के केस को फॉरेस्ट कलियरेंस के लिए initiate करें।	स्वास्थ्य/ लो0नि0/ वन विभाग
6.	राजकीय डिग्री कॉलेज मल्याणा में खोला जाए। भूमि उपलब्ध है। इसका फारेस्ट कलियरेंस केस शीघ्र तैयार करके कार्य शुरू किया जाए।	शिक्षा/वन विभाग
7.	संजौली में प्रस्तावित हैलीपेड की भूमि का FCA केस शीघ्र तैयार करके कार्य शुरू किया जाए।	नागरिक एवं उड्डयन/ वन विभाग
8.	हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी खोली जाए।	उच्च शिक्षा/युवा सेवाएं एवं खेल विभाग
9.	नया बसस्टैंड ढली को पीपीपी मोड में बनाया जाए।	HRTC/बस अड्डा प्राधिकरण
10.	नवबहार-शनान सड़क का जल्दी से सर्वे करके फारेस्ट केस बनाया जाए।	लो0 नि0 /वन विभाग
11.	समिट्री के पास लो0नि0वि0 के पुराने भवन को तोड़ कर साथ खाली पड़ी लगभग साढ़े चार बीघा भूमि पर पीपीपी मोड में कार पार्किंग बनाई जाए।	लो0 नि0/शहरी विकास
12.	भट्ठाकुफर चौक और कसुम्पटी बाजार नगर निगम क्षेत्र में हाई मास्क लाइटें लगाई जाएं।	नगर निगम शिमला/शहरी विकास विभाग
13.	पैदल चलने योग्य मार्ग कुफरी से चीनीबंगला का सुधार किया जाए।	वन/पर्यटन विभाग
3. श्री सुरेश भारद्वाज, शिमला		
1.	विधायक प्राथमिकता की जिन स्कीमों की डी0पी0आरस0 नहीं बनती उन्हें आउटसोर्स किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
2.	शिमला के लिए पीने का पानी चन्द्रनाहन या कोलडैम से आए। छोटी-2 स्कीमें जैसे बावड़ी इत्यादि को चलाने के लिए नगर निगम को पैसा दिया जाए। पीने के पानी के लिए अलग स्कीम हो तथा अन्य कार्यों के लिए ट्रीटमेंट प्लांट से पानी उपलब्ध करवाया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
3.	पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को modernize किया जाए व existing plants की मशीनरी व फिल्टरस को बदलने की जरूरत है। मल्याणा-चम्याणा को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाए। इस वर्ष के बजट में पीने के पानी और सीवरेज के लिए विशेष प्रावधान हो।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
4.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की बिल्डिंग की strengthening की जाए।	लो0 नि0/ स्वास्थ्य विभाग

5.	शिमला के congestion को दूर करने के लिए कुछ लिंक सड़कों को बाईपास सड़क से जोड़ा जाए। सुरंगों का निर्माण भी किया जाए।	लो0नि0 विभाग/ नगर निगम शिमला
6.	शिमला से सब्जी मण्डी दाढ़नी के बगीचे को शिफ्ट किया जाए।	मण्डी समिति/ कृषि विभाग
7.	शिमला शहर को अलग से कैपिटल फण्ड दें।	वित्त/शहरी विकास विभाग
8.	शिमला में बन्दर और कुत्तों की समस्या को दूर किया जाए।	नगर निगम /वन्य प्राणी विभाग
9.	H.R.T.C की लम्बी-2 बसों को शिमला में न चलाया जाए। जाम की समस्या को दूर करने के लिए sealed area टैक्सी बाकी जगह भी चलाएं।	HRTC

4. श्री रोहित ठाकुर, जुब्बल-कोटखाई

1.	ठियोग-खड़ापथर-हाटकोटी सड़क का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को दोबारा extension मिले। इसकी review meeting रखी जाए ताकि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर डेढ़ वर्ष में मुकमल हो सके। लालढांक-पावंटा साहिब-राजबन-रोहडू सड़क बद्रीपुर से कफोटा तक बन चुकी है तथा कफोटा से फैंडसपुल बाउन्ड्री तक टैन्डर हो चुके हैं जिसका कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा उत्तराखण्ड सरकार के साथ भी इस मामले को take up किया जाए। छैला-नेरीपुल-यशवंतनगर-ओछघाट-कुम्हारहट्टी सड़क जिसकी फंडिंग सीआरएफ के तहत होनी है, की स्वीकृति शीघ्र मिले। नारकण्डा-बागी-सुंगरी-खदराला -रोहडू सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्जा प्राप्त हो। मैहन्दली-टिक्कर सड़क के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	लो0नि0 विभाग
2.	जैसे ग्रामीण सड़कों को specification में relaxation दी है वैसे ही Snow bound area की सड़कों की specification में relaxation दी जाए जिससे AMP का बेहतर सदुपयोग होगा और अतिरिक्त सड़के मिलेंगी। फारेस्ट क्लीयरेंस केसों का शीघ्र निपटारा किया जाए तथा एक हैक्टेयर तक के केसों को liberally निपटाया जाए।	लो0नि0/वन विभाग
3.	डी0पी0आर0 में Choked Culverts की जगह causeway के निर्माण का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में पैसों का बेहतर सदुपयोग होगा और सड़के सुचारु रूप से चलेगी।	लो0नि0 विभाग
4.	मिनी सचिवालय बिल्डिंग कोटखाई के लिए अतिरिक्त फंडस का प्रावधान किया जाए।	सामान्य प्रशासन
5.	इस वर्ष आई0पी0एच0 को विशेष प्राथमिकता देनी पड़ेगी। खाली पदों को भरा जाए। आउटसोर्सिंग की नीति को खत्म किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

6.	दो वर्ष से सिंचाई स्कीमों (AIBP) की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है इसे कृषि विभाग के माध्यम से प्रधान मंत्री कृषि आदर्श योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजा जाए। छोटे डाई की पाईपों की कमी को दूर किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ कृषि विभाग
7.	जुब्बल-कोटखाई की कृषि सिंचाई योजना जिसके लिए लगभग 52 करोड़ रु० केन्द्र से स्वीकृत हो चुके हैं व क्षेत्र में लगभग 600 टैंक बने हैं। इस योजना की proper estimation न होने के कारण कुछ gaps आ रहे हैं तथा पानी टैंकों तक नहीं पहुंच रहा है। इन gaps को पूरा करने के लिए फंड का प्रावधान किया जाए ताकि पूरे जुब्बल-कोटखाई-टिक्कर क्षेत्र को इस सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त हो सके।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ कृषि विभाग
8.	विद्युत विभाग की कोटला-समोली-नोगली-आंधा मेन एचटी लाईन के लिए 19 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं तथा 66 केवी सबस्टेशन हाटकोटी के लिए भी बजट उपलब्ध है। इनका कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
9.	रोहड़ू, पतलीकुहल तथा खड़ापथर में सी०ए० स्टोर के लिए मांगी गई सिक्योरिटी के लिए धनराशि प्रदान की जाए।	उद्यान विभाग/HPMC
10.	टिक्कर में कॉलेज खोला जाए।	शिक्षा विभाग
11.	विधायक निधि को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग (R&DP Divn.)
12.	स्कूलों में S.M.C. के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती की जाए।	शिक्षा विभाग
5. श्री मोहन लाल बरागटा, रोहड़ू		
1.	जिस्कुन-जाखा सड़क के कार्य में तेजी लाई जाए।	लो०नि०वि०
2.	बिजली की समस्या का समाधान किया जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
3.	रोहड़ू में Permanent Additional District Session Judge Court खोला जाए।	गृह विभाग
4.	रोहड़ू बाजार में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए।	नगर परिषद रोहड़ू/शहरी विकास/लो० नि० विभाग
5.	रोहड़ू में लम्बी बसों को न चलाया जाए। बहुत से रूट बन्द हो चुके हैं, उन्हें बहाल किया जाए।	HRTC
6.	रोहड़ू में T.C.P. का कार्यालय खोला जाए।	नगर एवं ग्राम योजना विभाग
7.	रोहड़ू में सब्जी मण्डी का कार्य भी नहीं हुआ, जिसे आरम्भ किया जाए।	मण्डी समिति/कृषि विभाग
8.	रोहड़ू अस्पताल में 50 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा दी जाए तथा डॉक्टरों के आवास बनाए जाएं।	स्वास्थ्य/ लो०नि० विभाग
9.	किमोली में प्राथमिक स्कूल खोला जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा

		विभाग
10.	पर्यटन की दृष्टि से रोहडू को विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
4. जिला मण्डी		
1. श्री जय राम ठाकुर, सेराज		
1.	पिछले दो-तीन वर्षों में विधायक प्राथमिकता में डाली गई किसी भी योजना की डी0पी0आर0 नहीं बनाई गई। यह डी0पी0आर0 निजी भूमि या फॉरेस्ट क्लीयरेंस केस के कारण नहीं बन पा रही है। इस समस्या को दूर किया जाए। डी0पी0आर0 तैयार करने की समय सीमा निर्धारित की जाए तथा इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। पंचायत के माध्यम से बनी लिंक सड़कों की रखरखाव के लिए पैसे का प्रावधान किया जाए।	लो0नि0वि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	विधायक प्राथमिकता की सड़क मोटर योग्य पुल गांव सुराह ग्राम पंचायत भड़ाव का निर्माण किया जाए। शिकारी देवी की ओर जाने वाली सड़क सेराज विधानसभा क्षेत्र से होकर जाती है। लो0नि0वि0 इस सड़क पर कार्य करे क्योंकि अब यह सैंक्चुरी क्षेत्र से बाहर है। इस सड़क के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	लो0नि0 विभाग
3.	सड़कों और पब्लिक बिल्डिंग्स की मरम्मत/रख-रखाव के लिए विधायक निधि से भी पैसा दिया जाना दिशा निर्देशों में मान्य होना चाहिए।	योजना विभाग (R&DP Div)
4.	शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए तथा फिल्टर बैक बनाए जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
5.	पिछले वर्ष गोहर डिवीजन में बर्फ से जो क्षति हुई, वहां पर जो स्थानीय लेबर और छोटे ठेकेदारों ने काम किया था, उनकी पेमेंट नहीं हुई उसे शीघ्र किया जाए। गांव में अभी भी कई ऐसे घर हैं जहां बिजली नहीं है। कोई भी ऐसा गांव न छूटे, सभी जगह बिजली की आपूर्ति की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के क्षतिग्रस्त खम्बों और कंडक्टरज को बदलने की आवश्यकता है।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
6.	14वें वित्तायोग में पंचायतों को पैसा दिया जाता है लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदेश की ओर से पैसे का प्रावधान होना चाहिए।	पंचायती राज विभाग
7.	विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाया जाए तथा 30 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि की सीलिंग को हटाया जाए। DCP मदों से स्वीकृत योजनाओं के निर्माण के लिए पूरी स्वीकृत धन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।	योजना विभाग (R&DP Div)

2. श्री महेन्द्र सिंह, धर्मपुर		
1.	विधायक नीधि के पैसे को सरकारी खजाने में जमा न किया जाए। इस बारे उचित निर्णय लिया जाए।	समस्त उपायुक्त/योजना विभाग (R&DP Divn)
2.	Rain Water Harvesting Scheme-cum-LIS पारछू तथा LIS स्कीम काँसल व Flood Protection Work कांडापतन, धनेड़, शिवपुर, समौर जैसी बड़ी स्कीमों को भारत सरकार के मंत्रालय को 90:10 की फंडिंग में किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतू भेजी जाएं ताकि प्रदेश का पैसा इन स्कीमों में कम खर्च हो।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
3.	2013-14 तथा 2014-15 में धर्मपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा फ्लड आया। उसकी वजह से आज भी लो0नि0वि0 की कई सड़के बन्द है। पिछले वर्ष की प्राथमिकता में जो सड़के बनाने को दी थी उनकी डी0पी0आरस0 बनकर तैयार नहीं हुई इसे समयबद्ध किया जाए।	लो0नि0 विभाग
4.	सोन खड्ड के ऊपर 75 कि0मी0 स्पैन पुल जो आर0आई0डी0एफ0 में स्वीकृत हुआ लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हो रहा है जबकि 2014 में इसका पैसा आया हुआ है। विभाग को इस कार्य को मण्डी डिविज़न में ही रखे जाने बारे आदेश दिए जाएं तथा इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाया जाए।	लो0नि0 विभाग
5.	फ्लड के दौरान जो चार मजदूर मर गए उनका compensation का पैसा अभी तक नहीं मिला।	राजस्व विभाग
6.	पर्यटन को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा सैक्टर वाइज़ मास्टर प्लान बनाया जाए व भारत सरकार को स्वीकृति/फंडिंग के लिए भेजा जाए। इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है।	पर्यटन विभाग
7.	हाईडल पावर के दोहन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बनाया जाए।	MPP & POWER विभाग/ HPSEBL
8.	आने वाले समय में पानी की गम्भीर समस्या होने वाली है इस पर अभी से विचार किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
9.	Organic खेती पर विचार किया जाए।	कृषि/उद्यान विभाग
10.	आबकारी एवं कराधान विभाग Excise policy में सुधार करके राजस्व में भी वृद्धि करने के उपायों पर विचार करें।	आबकारी एवं कराधान विभाग
11.	उप तहसील टीहरा के क्षेत्र को सरकाघाट से जोड़ा जाए।	राजस्व/ सामान्य प्रशासन

3. श्री इन्द्र सिंह, सरकाघाट		
1.	योजनाओं की डी०पी०आर० शीघ्र तैयार की जाएं ताकि विकास कार्य तीव्र गति से हो सके।	लो०नि०वि०/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	सड़कों की हालत बहुत खराब है व उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। सड़कों की मरम्मत के कार्यों के लिए दिया गया पैसा गुणवत्ता के आधार पर खर्च नहीं हो रहा है। लिंक रोड्स की maintenance के लिए फंड दिया जाए।	लो०नि० विभाग
3.	ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं व दिए गए कार्यों को वह आगे कमीशन लेकर sublet कर देते हैं। इस प्रथा को खत्म किया जाए। जो ठेकेदार टेंडर अवार्ड होने पर कार्य नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।	लो०नि०वि०/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
4.	कई गांवों में अभी भी पानी की कमी हो रही है। पानी के स्रोतों को कैसे बचाया जा सकता है इस पर सरकार ध्यान दें तथा सिस्टम को रिचार्ज करने बारे जोन वाइज सर्वेक्षण किया जाए कि किस जोन में पानी की ज्यादा कमी है। छोटी-2 पुरानी कुहलों को revive किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ ग्रामीण विकास/पंचायती राज
5.	आई०पी०एच० व लो०नि० विभाग द्वारा infeasible स्कीमों की डी०पी०आर० न बनाई जाए। उठाऊ सिंचाई योजना की तीनों स्कीमों बन्दरौड़, बनवाहर तथा बलियारा का कार्य पूरा किया जाये।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	सीर खड्ड से हो रहे भारी नुकसान को मद्येनजर रखते हुए इसके तटीयकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए तथा फंड्स का प्रावधान किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
7.	सरकाघाट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसको शीघ्र पूर्ण किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/शहरी विकास विभाग
8.	सरकाघाट पी०एच०सी० में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए। Gynaecologist के पद को भरा जाये। सरकाघाट में मैडिकल विशेषज्ञ नहीं है। बल्दाड़ा पी०एच०सी० में एडमिनिसट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण किया जाए। जंझैल पंचायत में आयुर्वेदिक डिसपेंसरी खोली जाए।	स्वास्थ्य /लो०नि०/ आयुर्वेदा विभाग
9.	स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी है। सीनियर स्कूल पौटा का मेन ब्लॉक भवन असुरक्षित है उसका शीघ्र पुर्ननिर्माण किया जाए।	प्रारम्भिक / उच्च शिक्षा विभाग
10.	कृषि योग्य खाली भूमि को कृषि के उपयोग में लाया जाए।	कृषि विभाग
11.	सैनिक कल्याण बोर्ड में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए।	सैनिक कल्याण विभाग
12.	बी०एस०एन०एल० में कॉल ड्राप को खत्म किया जाए।	सामान्य प्रशासन/ बी०एस०एन०एल०

5. जिला कुल्लू

1. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, मनाली

1.	बिजली बोर्ड सब स्टेशन प्रीणी को लैन धौरन विद्युत परियोजना से जोड़ें जिससे क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर हो जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
2.	मनाली गांव में आलू ग्राउंड को बाहन से लेकर जगतसुख तक सारे क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ने बारे 101 करोड़ रु० की डी०पी०आर० तैयार है। इसकी फंडिंग की विभाग व्यवस्था करे।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ शहरी विकास विभाग
3.	बिजली महादेव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की 90 करोड़ की डी०पी०आर० बनकर तैयार है परन्तु इसमें कुछ आपतियां लगाई गई हैं जिसे विभाग तुरन्त दूर करें।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
4.	मनाली अस्पताल को 50 बिस्तरों वाला कर दिया है। भवन की कमी है। मनाली अस्पताल की अपनी डेढ़-दो बीघा से भी कम जमीन है इसलिए साथ लगते 7 बीघा भूमि को स्वास्थ्य विभाग के नाम करके यह कार्य शीघ्र किया जाए।	स्वास्थ्य/ राजस्व विभाग
5.	मनाली में पार्किंग की समस्या को दूर किया जाए। लोक निर्माण विभाग की 7 बीघा भूमि पर मल्टीपर्पज भवन शीघ्र बनाया जाए या उस पर पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ लोक निर्माण विभाग
6.	राजकीय सीनियर सैकेन्डरी स्कूल जगतसुख, राजकीय उच्च पाठशाला पलवान तथा राजकीय सीनियर सैकेन्डरी स्कूल भेखली में फंड की कमी को दूर किया जाए। राजकीय सीनियर सैकेन्डरी स्कूल रायसन में अतिरिक्त कमरों के लिए भी फंड का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग
7.	पतलीकूहल में पी०एच०सी० खोला जाए। कटराई आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन को जल्द पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य/ आयुर्वेद /लोक निर्माण विभाग

2. श्री खूब राम, आनी

1.	योजनाओं की डी०पी०आर० को शीघ्र तैयार किया जाए।	लो०नि० वि०/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	सराहन-बागीपुल-बठाड़ सड़क के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।	लो०नि० विभाग

3.	आई0पी0एच0 डिवीजन आनी में जे0ई0 के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
4.	एग्रीकल्चर/हॉल्टीकल्चर विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए।	कृषि/उद्यान विभाग

6. जिला बिलासपुर

1. श्री बम्बर ठाकुर, बिलासपुर

1.	लो0नि0वि0 की लम्बित डी0पी0आरस0 को शीघ्र तैयार किया जाए।	लो0नि0 विभाग
2.	सड़कों के फारेस्ट क्लीयरेंस की एक हैक्टेयर तक की पावर डीएफओ को दे दी जाए।	लो0नि0/ वन विभाग
3.	मोरसिंगी पंचायत में कसोल गांव में पी0एच0सी0 के लिए एक हैक्टेयर तक जमीन चाहिए जिसके लिए NOC नहीं मिल रही है।	स्वास्थ्य/ राजस्व विभाग
4.	रैफरल अस्पताल बिलासपुर के 37 लाख रु0 लो0 नि0 वि0 की इलैक्ट्रिक डिवीजन ऊना के पास पड़े हैं और उनसे बार-2 अनुरोध करने पर भी फण्ड प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है इसकी जांच करवाई जाए।	स्वास्थ्य/लो0 नि0 विभाग
5.	बिलासपुर में हाईड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज बंदलाधार के लिए फण्ड दिया जाए।	तकनीकी शिक्षा
6.	Pot holes के काम ठेकेदारों को दिए लेकिन काम नहीं हुए, इसकी जांच करवाई जाए।	लो0नि0 विभाग

2. श्री रणधीर शर्मा, श्री नैनादेवी जी

1.	विधायक प्राथमिकता की पिछले तीन साल से छः लिंक सड़कों जैसे खलोटा-गुड़घान से गांव मुमलुधार, बस्ती से गवांडर, पंचकोरा से कलरु कोठी, पांजीपीरा से सोनी का सर्वेक्षण करवाकर डी0पी0आरस0 शीघ्र बनाई जाए और फारेस्ट क्लीयरेंस के मामले शीघ्र निपटाए जाएं।	लो0नि0/ वन विभाग
2.	पटवारियों की कमी को दूर किया जाए।	राजस्व विभाग
3.	नालसू नाला से खालसी सड़क दाइलामोड़ से बैरी नाला की ओर की हालत बहुत खराब है इसकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। प्रमुख सड़क ब्रह्मपुखर से नौणी की हालत भी बहुत खराब है। जिन सड़कों के साईड में टैलीकॉम विभाग ने नालियां बनाई हैं, उनकी रिपेयर की आवश्यकता	लो0नि0 विभाग

	है। लिंक रोड की हालत बहुत खराब है इसके लिए पैसे को डीविजन वाइज़ खर्च करें। तीन सड़कें देवथ-डाबर सड़क, NH जामली-नेरी सड़क तथा कोठीपुरा सड़क बनकर तैयार नहीं हुई हैं।	
4.	आई0पी0एच0 विभाग ने रेन वॉटर हारवैस्टिंग सट्रक्चर का कार्य शुरू नहीं किया है।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
5.	पीने के पानी के टैंकों को ढकने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	बिजली विभाग में सर्वेयर, जे0ई0 तथा फिट्टर के खाली पदों को भरा जाए ताकि काम सुचारु रूप से चलता रहे।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
7.	सी0एच0सी0 ग्वान्डल, श्री नैनादेवी जी, इत्यादि में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को जल्द भरा जाए।	शिक्षा विभाग
9.	सरकारी unproductive Expenditure को कम किया जाये।	वित्त विभाग
7. जिला कांगड़ा		
1. श्री मनोहर धीमान, इंदौरा		
1.	पिछले दो वर्षों से लो0नि0वि0 की एक भी डी0पी0आर0 नहीं बनी। लो0नि0वि0 में पिछले दो वर्षों से कुछ सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है तथा पैच वर्क का कार्य भी नहीं हुआ है। विभाग में जे0ई0 तथा लेबर के पद भरे जाएं ताकि कार्य सुचारु रूप से चल सके।	लो0नि0 विभाग
2.	आई0पी0एच0 विभाग में जे0ई0, फिट्टर तथा लेबर के खाली पड़े पदों को भरा जाएं।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
3.	बिजली विभाग में लाईनमैन तथा टीमेट के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जल्दी से स्टाफ की भर्ती की जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
4.	डमटाल-इन्दौरा वाया कन्दोणी सड़क के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए। प्रमुख सड़कें जैसे गंगथ-इन्दौरा सड़क, गंगथ-इन्दौरा-काठगढ़ सड़कों की रिपेयर की जाए। ठाकुरद्वारा से पराल सड़क, इन्दौरा से पराल सड़क, चक्कयाड़ा से रैन सड़क में बरसात का पानी व मिट्टी भर जाती है। इसकी भी रिपेयर की जरूरत है।	लो0नि0 विभाग
2. श्री संजय रतन, ज्वालामुखी		
1.	विधायक प्राथमिकता में नाबाई की लिमिट को 100 करोड़ तक बढ़ाया जाए।	योजना विभाग (RIDF Div.)

2.	चंगर क्षेत्र में बहुत सी सड़कें व पुल बनने हैं उसके लिए कम से कम 50 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।	लो0नि0 विभाग
3.	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए ।	समस्त विभाग
4.	खुंडिया को सी0एच0सी0 घोषित किया गया था लेकिन इसका कार्य शुरू नहीं हुआ।	लो0नि0/ स्वास्थ्य विभाग
5.	देहरा का डिवीजन बहुत बड़ा है लेकिन वहां 6 लेबर भी नहीं है। लो0नि0वि0 तथा आई0पी0एच0 विभाग में लेबर की कमी को पूरा किया जाए। बेलदार कलर्क का कार्य कर रहे हैं तथा चौकीदार भी नहीं है।	लो0नि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	सड़कों की टारिंग की जाती है लेकिन वह जल्दी खराब हो जाती है इसलिए इसके quality work पर ध्यान देने की जरूरत है।	लो0नि0 विभाग
7.	आई0पी0एच0 की बड़ी स्कीमों को सैंकशन होने में बहुत टाईम लगता है इसलिए सभी चुनाव क्षेत्रों को हैण्डपम्प तथा सोलर लाईट्स के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ हिम ऊर्जा
8.	चंगर क्षेत्र में देहरियां या लगडु में 33 केवी का सब स्टेशन चाहिए। ज्वालामुखी में तारों का बहुत बड़ा जंजाल फंसा है। एलटी को रिमूव करके केबल का प्रावधान ज्वालाजी शहर में किया जाए।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
9.	चंगर क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुधारा जाए। शटल बसों को दिया जाए ताकि लोगों को मेन स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा हो और वहां से लौंग रुट की बसों को ले सकें।	HRTC
10.	ज्वालामुखी क्षेत्र के लिए एक पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाए।	तकनीकी शिक्षा
11.	ज्वालामुखी में आई0पी0एच0 का एक डिवीजन खोला जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
3. श्री नीरज भारती, ज्वाली		
1.	छोटी आबादी वाले गांव में पानी की बड़ी स्कीम बनाने की जगह छोटी-2 स्कीमें बनाई जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाए जाने चाहिए इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान हो।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	नूरपुर सर्कल में वॉटर कैरियरस व पम्प ऑपरेटरस को डिवीजन लेवल पर आउटसोर्स द्वारा तैनात किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4. श्री यादविन्द्र सिंह गोमा, जयसिंहपुर		
1.	जयसिंहपुर में कुछ सड़कें बहुत दयनीय स्थिति में हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र और जयसिंहपुर के बीच में एक बड़ी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना था इसका फाउन्डेशन स्टोन भी रखा जा चुका है लेकिन उसमें विवाद के कारण टेंडर नहीं हुआ। इसका कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए। भवारना से हारसीपत्तन सड़क को स्टेट रोड प्रोजेक्ट में डाला गया था जिसका कार्य जुंगादेवी में ही रुक गया है।	लोक निर्माण विभाग
2.	पिछले वर्ष पी०एच०सी० पंचरुखी को सी०एच०सी० लैवल बनाने के लिए 50लाख का अतिरिक्त बजट दिया गया था जिसकी अभी ड्राईंग भी तैयार नहीं हुई, टैंडर भी नहीं लगा है। आयुर्वेदिक अस्पताल कोसरी को सी०एच०सी० लैवल बनाने के लिए 50लाख तक का अतिरिक्त बजट दिया गया था जिसकी अभी ड्राईंग या टैंडर approve नहीं हुआ है। जब तक इस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं होता है तब तक यह अस्पताल चौबीस घण्टे खुला रहना चाहिए जिसमें रात-दिन दो डॉक्टर होने चाहिए। पी०एच०सी० भवाना में डॉक्टर, नर्स तथा चपड़ासी की appointment की जाए। पी०एच०सी० मझेरा के भवन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। सी०एच०सी० खैरा स्टेट हाईवे पर पड़ता है वहां पर भवन की कमी है वहां के लिए भी धन का प्रावधान किया जाए।	स्वास्थ्य/ आयुर्वेद/ लोक निर्माण विभाग
3.	आई०टी०आई० लाडू का फाउन्डेशन स्टोन रखा गया लेकिन इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है।	तकनीकी विभाग
4.	जयसिंहपुर में बसस्टैंड के लिए 50 लाख दिया गया है, भूमि उपलब्ध है लेकिन कार्य आरम्भ नहीं हुआ।	HRTC /बस अड्डा प्राधिकरण
5.	कम्बाईड ऑफिस/मिनी सचिवालय जयसिंहपुर का एक भवन बनाया जाए।	सामान्य प्रशासन/ राजस्व विभाग
6.	स्टेट हाईवे रोड धर्मशाला से लेकर सरी मोड़ पर हारसीपत्तन पुल पर खत्म होता है, उस पर एक सिंगल रोड पंचरुखी-करोड़ी-भवाना तक पांच कि०मी० का स्ट्रैच है उसकी कटिंग के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। लिंक रोड के maintenance के लिए धन का प्रावधान किया जाए। PMGSY की एक सड़क, बालकरूपी से दाबी की हालत बहुत खराब है। चंगर क्षेत्र में तीन पंचायतें, लाडू, कुहण तथा बालकरूपी के छः गांव disconnect हो रहे हैं इसमें एक तरफ ज्वालामुखी तथा दूसरी तरफ सुलह चुनाव क्षेत्र है वहां पर बलून्दर से सुजानपुर नदी पर foot bridge बनना है जो वर्तमान में foot bridge है उसे सुलह चुनाव क्षेत्र में	लोक निर्माण विभाग

	शिफ्ट किया जाए तथा वहां का foot bridge ज्वालामुखी में लाया जाए।	
7.	पिछले साल की विधायक प्राथमिकता में आई0पी0एच0 Division पालमपुर में सिंचाई तथा पीने के पानी की कोई भी डी0पी0आर0 नहीं बनी है।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
5. श्री जगजीवन पाल, सुलह		
1.	लो0नि0वि0 तथा आई0पी0एच0 विभाग में टैन्डर प्रोसेस में बहुत देरी हो रही है। पिछले साल न्यूगल खड्ड के ऊपर चलाह पर सड़क का शिलान्यास हुआ था लेकिन अभी तक टैन्डर नहीं हुआ है। टैन्डर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।	लो0नि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
2.	खरोट में टैक्नीकल एजुकेशन के नाम लगभग 53 कनाल जमीन है वहां पर जनता द्वारा 3 करोड़ रु0 जमा करके लगभग 15 कलासरूम बनाए गए हैं। यह जगह नैशनल हाईवे के साथ है। यहां पर कोई टैक्नीकल/ एजुकेशनल संस्थान बनाया जाए।	तकनीकी विभाग
3.	स्कूलों में जो वी0आर0सी0 लगाए गए हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं क्योंकि यह पद भारत सरकार से भरे गए हैं तथा इनकी जगह कोई और अध्यापक नहीं आए। जिसकी व्यवस्था की जाए।	शिक्षा विभाग
4.	राजकीय महाविद्यालय थुरल के भवन के लिए रु0 3.00 करोड़ का प्रावधान 2016-17 के बजट में किया जाए।	शिक्षा विभाग
5.	सुलह के ग्राम पंचायत बनोट में पी0एच0सी0 की घोषणा की गई थी जिसका कार्य आरम्भ किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	विधवा या अपंग लोग जो वॉटर कैरियर लगाए गए थे, उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया गया। परन्तु उनके रिटायर होने के बाद उनके स्थान पर किसी को भी नहीं लगाया जा रहा है। अतः विधवाओं और अपंगों को वॉटर कैरियर लगाए जाने पर उनका भला हो सकता है।	शिक्षा विभाग
7.	आई0पी0एच0 विभाग में फील्ड वर्कर्स की बहुत कमी हो गई है। वाटर गार्ड को दैनिक वेतन भोगी किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
6. श्री किशोरी लाल, बैजनाथ		
1.	शिव मन्दिर बैजनाथ में लैंड स्लाईडिंग को रोका जाए।	लो0नि0 विभाग
2.	बिनवा खड्ड पर खीरगंगा घाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। उसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए।	पर्यटन विभाग
3.	बैजनाथ से चवीन सड़क में रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि एक फाटक बन जाए। उतराला से होली सड़क के शेष बचे काम को जल्दी पूरा करें। यह सड़क बड़ाभंगाल तक जाती है और वहां विद्युत उत्पादन	लोक निर्माण/ विद्युत विभाग/ HPSEBL

	की अपार सम्भावना है जिससे भविष्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।	
4.	बैजनाथ के पपरोला क्षेत्र में सीवरेज तथा बाईपास की बहुत आवश्यकता है। पपरोला से बैजनाथ तक बाईपास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ शहरी विकास/लो0नि0 विभाग
5.	बैजनाथ-करनाथू-सराजला-भरेड़ सड़क को जोड़ा जाए ताकि तपवानी गर्म पानी के चश्में को विकसित किया जाए और पर्यटक ज्यादा से ज्यादा वहां आए। उतराला-जालसू मार्ग थोड़ा सा बनने को है, यदि उसे विकसित किया जाए तो पर्यटन के लिए एक अच्छा आकर्षक स्थान बन सकता है।	लो0नि0/ पर्यटन विभाग
6.	बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग की तर्ज पर थाथी-बराहन सड़क का निर्माण करके वहां बिलिंग से अच्छा पैराग्लाइडिंग स्थल बन सकता है। बैजनाथ-बरेड़-राजगुंदा सड़क को कुनी से जोड़ा जा सकता है। इसे विधायक प्राथमिकता में भी डाला गया था। यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो वहां भी पर्यटन की अपार सम्भावना है। भरोट-मारड़ी सड़क की हालत बहुत खराब है इस सड़क को पक्का किया जाए। सुगुर-भानग-खड़याल सड़क में बिनवा नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाए जिससे इलाके की दूरी कम होगी तथा कॉलेज जाने वाले छात्र आसानी से आ जा सकेंगे।	Mountaineering and Allied Sports/ लो0नि0/ पर्यटन विभाग
7.	बैजनाथ बसस्टैंड का काम शीघ्र शुरू किया जाए। तथा वर्कशॉप के लिए जगह उपलब्ध है, उसके भवन का निर्माण किया जाए।	HRTC/बस अड्डा प्राधिकरण
8.	निर्वाचन क्षेत्र में कई गांव बस सुविधा से वंचित हैं। वहाँ पर बसें चलाई जाएं।	HRTC
9.	पुरानी कुहलों की रिपेयर नहीं हो रही है, इनकी maintenance की जाए जिससे पानी की कमी न आए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ उपायुक्त
10.	बैजनाथ अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। वहां ऑपरेशन न होने की वजह से टांडा जाना पड़ता है व इससे लोगो को भारी परेशानी होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होते। वहां पर डाक्टर तथा अन्य स्टाफ की व्यवस्था सही ढंग से की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11.	चौबू बल्ह विद्युत परियोजना को बनाया जाए जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकें।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
12.	बड़ाभंगाल में सड़क नहीं है जिसके कारण गरीबों को बीमार हालत में बिना इलाज ही रहना पड़ता है। वहां के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाए।	सामान्य प्रशासन/ लो0नि0 विभाग
13.	बैजनाथ में इंदिरा गांधी स्टेडियम को Develop किया जाए ताकि हेलीकॉप्टर वहां उतर सके।	नागरिक उड्डयन/ युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

8. जिला लाहौल-स्पीति

1. श्री रवि ठाकुर, लाहौल-स्पीति

1.	लाहौल स्पीति में हेलिकॉप्टर की सुविधाएं on demand दी जाएं।	जनजातीय विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	लाहौल स्पीति में 50 प्रतिशत डाक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, कोई सर्जन डॉक्टर नहीं है। डिसपेंसरी में भी डाक्टर नहीं है। केलॉग में सरपल्स डाक्टरों को फील्ड में भेजा जाए। फील्ड में ऑर्डर नहीं आए हैं। डॉक्टर मौनिका को लाहौल शिफ्ट किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	परिवहन विभाग के कर्मचारी, XENs व विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी TAC बैठक में नहीं आते हैं। विद्युत विभाग को जो बजट दिया जाता है वो डिमांड से 10 प्रतिशत से भी कम है, उसे वो DC/ADC से पूछकर ही खर्च करें।	जनजातीय विकास/विद्युत विभाग/ उपायुक्त
4.	आई0पी0एच0 और लो0नि0वि0 के लिए बजट कम है। additionality के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
5.	लाहौल स्पीति में मोनोकॉप होने के कारण 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाए।	कृषि/ जनजातीय विकास विभाग
6.	बजट में Power Sprinklers & Power Tillers के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।	कृषि/ जन जातीय विकास विभाग
7.	स्पीति नदी का चैनेलाईजेशन किया जाए ताकि इसके दोनो तरफ अधिक औषधीय पौधे लगाए जा सकें।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/उद्यान/ आयुर्वेद विभाग
8.	लाहौल स्पीति को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए।	जन जातीय विकास विभाग
9.	सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है तथा दिल्ली से 32 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तीव्र गति से करें।	जन जातीय विभाग
10.	लो0नि0वि0 और आई0पी0एच0 के FCA और FRA cases बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। इस बारे निर्देश जारी किए जाएं। मुदभावा सड़क के लिए क्लीयरेंस की आवश्यकता है।	लो0 नि0/वन/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

11.	नाबार्ड सीलिंग बढ़ाकर 100 करोड़ की जाए।	योजना विभाग (RIDF Div.)
12.	आयुर्वेदा विभाग में गाड़ी दी जाए ।	आयुर्वेदा/ जन जातीय विकास विभाग
13.	लाहौल-स्पीति भवन मनाली आई0पी0एच0 विभाग से वापिस उपायुक्त लाहौल-स्पीति को दिया जाए।	उपायुक्त लाहौल-स्पीति/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
14.	कृषि विभाग द्वारा लगाए गए ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं, उन्हें चालू किया जाए।	कृषि विभाग

9. जिला किन्नौर

1. श्री जगत सिंह नेगी, किन्नौर

1.	जन जातीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार से फंड आना चाहिए। NHRM या SSA से फंडिंग होनी चाहिए।	जन जातीय विकास/ स्वास्थ्य/ शिक्षा विभाग
2.	फॉरेस्ट कन्ज़र्वेशन ऐक्ट के तहत अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र के नौतोड़ तथा FCA के केस बनने हैं व इसमें ट्राईबल क्षेत्र में 12 बीघे भूमि तक DFOs को पावर होगी। इस बारे शीघ्र कार्यवाही की जाए।	वन विभाग

10. जिला चम्बा

1. श्री हंस राज, चुराह

1.	चम्बा से तीसा, पांगी की ओर सड़क को स्टेट हाईवे रोड घोषित किया गया है। इस सड़क में passes लेने में भी दिक्कत हो रही है। पिछले 2-3 महीनों में 15-16 दुर्घटनाएं हो चुकी है क्योंकि आगे हाईड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है वहां के लिए बड़े वाहन जाते हैं। इसका काम हो रहा है लेकिन इसे और ज्यादा गति देने की आवश्यकता है। इसके एक तरफ जम्मू कश्मीर का बार्डर एरिया लगता है। हाल ही में पठानकोट की आतंकवाद की घटना को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे हमलों को रोकने के लिए आर्मी को ऐसी जगह पहुंचाने के लिए या depute करवाने के लिए सड़क की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है।	लो0नि0 विभाग
----	---	--------------

2.	SPOs का मानदेय बढ़ाया जाए।	गृह विभाग
3.	सी0एच0सी0 तीसा को FRU का दर्जा दिया जाए। तथा वहां Gynaecologist एवं Child Specialist नियुक्त किये जाएं। मसरुन तथा बैरागढ़ के लिए सी0एच0सी0 दी जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	एस0एम0सी0 और पी0टी0ए0 अध्यापकों के लिए नीति बनाई जाए।	प्रारम्भिक/ उच्च शिक्षा विभाग
5.	बिजली के पुरानी तारों व खम्भों को बदला जाए। हाइड्रो प्रोजेक्ट सुजियात की बिजली कोटला के आठ पंचायतों के लोगों को ही मिले तथा चुराह में पैदा होने वाली बिजली का लाभ पूरे चम्बा को मिले जिससे बाहर से बिजली न लानी पड़े।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
6.	चुराह क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी तथा पुष्प उत्पादन की भारी क्षमता है। वहां पर औषधीय पौधे लगाए जाएं ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके।	कृषि/उद्यान/ आयुर्वेद/वन विभाग
7.	पर्यटन की दृष्टि से चुराह क्षेत्र में बहुत क्षमता है पहाड़ी क्षेत्र जैसे सतरुंडी, रानी कोट, इत्यादि को विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
8.	करेरी, चड़ोरी, कलेहल सड़क का कार्य नहीं हुआ है। कुटेड़ सड़क PMGSY के अन्तर्गत लम्बित पड़ी है। आईल तथा सनवाल का मकरछछूंद का इलाका बार्डर के साथ लगता है, यहां के लिए सड़क अति आवश्यक हो गई है। गोयला बनौडी जहां ऐतिहासिक गोम्पा है वहां के लिए सड़क के माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	लोक निर्माण/ पर्यटन विभाग
9.	तीन-2, चार-2 पंचायतों में कोई भी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नहीं है। आवश्यकतानुसार स्कूलों की upgradation की जाए।	शिक्षा विभाग/ प्रारम्भिक शिक्षा
10.	Atheletics को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाए।	युवा सेवाएं एवं खेल विभाग
11.	चुराह का ज्यादातर क्षेत्र पिछड़ा है वहां पर Solar Power Project लगने थे जो अभी तक नहीं लगे। हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, investors को प्रोत्साहित किया जाये।	विद्युत विभाग/ HPSEBL/हिम ऊर्जा
12.	चुराह चुनाव क्षेत्र में सब-तहसील बनाई जाए।	राजस्व विभाग
13.	चुराह चुनाव क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोला जाए।	शिक्षा विभाग
2. श्रीमती आशा कुमारी, डलहौजी		
1.	चम्बा में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। प्रशिक्षित बेरोजगार बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षित युवा खेतों में भी काम करना पसंद नहीं करते हैं तथा उनको Job Oriented प्रशिक्षण दिया जाए व Job opportunities भी सृजित की जाएं। HPPCL को सुंगला सुरगानी 48 मैगावाट का प्रोजेक्ट दिया है	श्रम एवं रोजगार विभाग/ HPPCL

	उसकी फंडिंग को शीघ्र Tie-up किया जाए।	
2.	N.H.P.C. और दूसरे प्रोजेक्टों ने हिमाचल सरकार की बहुत सी जमीन construction/commissioning के समय acquire की थी अब वह जमीन un-utilized पड़ी है उसे या तो सरकार अपने पास ले लें या किसानों से एक निश्चित धनराशि लेकर उनको वह जमीन वापिस दी जाए।	राजस्व/विद्युत विभाग/ उपायुक्त
3.	गौ सदन बनाने में भूमि का स्थानांतरण बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ज्यादातर जमीन वन भूमि है तथा इसके स्थानांतरण में बहुत समय लग रहा है। इसके लिए कोई सरल रास्ता निकाला जाए। जहां मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन है उस बारे में विचार किया जाए।	पंचायती राज/ राजस्व/वन/ पशुपालन विभाग
4.	लोगों द्वारा सड़कों के किनारे कटान करने के लिए डम्पिंग साइट्स को earmarked किया जाए।	लो0नि0 विभाग
5.	स्टेट इनफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के माध्यम से सलूनी एवं अन्य स्थानों पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाए।	स्टेट इनफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड/ शहरी विकास/ लो0नि0 विभाग
6.	सलूनी हैलीपैड के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाए।	नागरिक उड्डयन विभाग
7.	100 बिस्तर अस्पताल चम्बा, बाथली तथा डाक्टर क्वार्टर/स्टाफ क्वार्टर के लिए administrative approval & Estimate Sanction दी जाए। इसके लिए पैसा sanction हो गया है। सलूनी के F.R.U. के लिए भूमि स्थानांतरण शीघ्र किया जाए।	स्वास्थ्य/ राजस्व विभाग
8.	बनीखेत की पॉलीटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसा उपलब्ध है, land स्थानांतरण हो गई है। भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	तकनीकी शिक्षा
9.	कुछ मॉडल स्कूल घोषित हुए थे, इसके लिए फंडिंग का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग/ प्रारम्भिक शिक्षा
10.	सीमेंट प्लांट चम्बा के लिए भूमि का प्रावधान किया जाए।	राजस्व/ उद्योग विभाग
3. श्री विक्रम सिंह जरयाल, भटियात		
1.	ब्लॉक में कोई B.D.O. नहीं है, B.D.O. की तैनाती की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
2.	विधायक प्राथमिकता में डाली गई स्कीमों की डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार की जाए। सुन्धा-जोनला सड़क को विधायक प्राथमिकता में डाला था, वहां खड्ड के ऊपर पुल बनना था। इस खड्ड में हर साल कई मौतें हो जाती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इस सड़क की डी0पी0आर0 भी नहीं बनी है। 2013-14 में विधायक प्राथमिकता में	लो0नि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

	डाली गई 16 कि०मी० सड़क चक्की से चम्बा की डी०पी०आर० नहीं बनाई गई। चुवाड़ी से हवाल सड़क के रास्ते पर तोहरू नाला पर एक ब्रिज बनना है जिसकी डी०पी०आर० नहीं बनी है। सांझीनाला पुल का कार्य पिछले तीन साल से चल रहा है, पैसा उपलब्ध है, लेकिन ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा है इसके कार्य को शीघ्र पूरा करें।	
3.	चुवाड़ी को तहसील का दर्जा दिया जाए।	राजस्व विभाग
4.	सुन्था में कॉलेज जल्द खोला जाए।	शिक्षा विभाग
5.	पी०एच०सी० समोट को सी०एच०सी० का दर्जा दिया जाए। सी०एच०सी० चुवाड़ी में स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	राजकीय उच्च पाठशाला मनहोता को प्लस टू बनाया जाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूण्डी में अध्यापकों की कमी है। स्कूलों में वार्षिक समारोह दिसम्बर से पहले खत्म करवा दें।	शिक्षा विभाग
7.	लो०नि०वि०, स्वास्थ्य तथा आई०पी०एच० में स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।	लो०नि०/ स्वास्थ्य/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
8.	चुवाड़ी में पानी की बहुत कमी है। टैंक में पानी लीक हो रहा है। टैंक तथा पाईपों को बदलने की जरूरत है। पानी की कमी को दूर किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
9.	लो वोल्टेज की बड़ी समस्या है। कुछ पिछड़ी पंचायतें जैसे ग्राम पंचायत जंझोग, मनहोता, सुकड़ा, परसयाड़ा, काली मरुंडा जीना तथा जैण में बिजली लाईनों की तारें अभी तक पेड़ों के साथ लटकाई गई हैं। खेतों में बिजली की तारे पड़ी हैं। बिजली के खम्भों को बदलने की जरूरत है।	विद्युत विभाग/ HPSEBL
10.	डी०सी० के पास जो LADA का पैसा आता है उसे प्रभावित क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाये।	उपायुक्त चम्बा
11.	आंगनबाड़ी केन्द्र टिल्ले पर बनाई गई है उसके लिए क्यों धन स्वीकृत किया गया।	उपायुक्त चम्बा/ महिला एवं बाल विकास विभाग
12.	राजकीय मिडल स्कूल गोदरा के लिए लैंड ट्रांसफर नहीं हुई है, वहां स्कूल के ऊपर छत नहीं है। बच्चे खुले में पड़ रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूलों की जमीन स्कूल के नाम पर ही नहीं है।	प्रारम्भिक/ उच्च शिक्षा/ राजस्व विभाग
13.	बनेड़ पंचायत में कोई भी उचित मूल्य की दुकान नहीं है, गांव चकोली में एक डीपो खोला जाए। गांव चक्की, चकोली, भौंट कुफरु में मोबाईल दुकान खोली जाए ताकि डीपो होल्डर वहां जाकर लोगों को सामान दे सकें।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
14.	कुंजर महादेव को पर्यटन की दृष्टि से Develop करने के लिए वहां चारों तरफ रेलिंग लगाई जाएं, बाथरूम तथा कमरे बनाए जाएं।	उपायुक्त चम्बा/ पर्यटन विभाग

15.	भटियात में sports academy बनाई जाए।	युवा सेवाएं एवं खेल विभाग
16.	हाईडल प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं और जो MOU साईन हुआ था उसके मुताबिक न तो लोगों के रास्ते साफ किए गए, न कुल्हे साफ हुई, यहां तक कि लोगों को 15 प्रतिशत पानी भी नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को जरूरत के अनुसार भी पानी नहीं मिल रहा है। फिनासिंह सिंचाई प्रोजेक्ट लाडू ग्राम पंचायत परछोड़ में बनाया गया है। जब यह प्रोजेक्ट बना तो एक MOU साईन हुआ जिसमें एक लाख प्रति बिसवा मुआवजा दिया जाना था, लेकिन वह दस हजार से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। वहाँ पर डम्पिंग प्वाइंट नहीं है पूरा मलबा खड्डों में फेंका जा रहा है। इन प्रोजेक्टों में जिन किसानों की जमीन आई है उन्हें उसका उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ विद्युत विभाग/ उपायुक्त
17.	जिला चम्बा में 1954 में बन्दोबस्त हुआ था, उसके बाद बन्दोबस्त नहीं हुआ है। लोगो की तकसीम, निशानदेई के मामले लम्बे समय से लटके पड़े हैं। वहाँ का बन्दोबस्त होना बहुत जरूरी है, इसे शीघ्र करवाया जाए।	राजस्व विभाग
18.	सिकरीधार में सीमेंट प्लाट के लिए भूमि का प्रबन्ध किया जाए ताकि जिला चम्बा की निर्धनता दूर हो सके।	राजस्व विभाग/ उद्योग विभाग
19.	निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
20.	निर्वाचन क्षेत्र में औषधीय पौधे मिट्टी को टेस्ट करके लगाए जाएं ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।	वन/उद्यान/आयुर्वेद विभाग
21.	ट्राउट मछली पालन के लिए लोगो को जागरूक किया जाए। ताकि लोगो को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।	मत्स्य विभाग
22.	निर्वाचन क्षेत्र में गरनोट आई0टी0आई0 में तीन ही ट्रेड हैं। वहां पर तीन ट्रेड और बढ़ाए जाएं तथा बिल्डिंग बनाने के लिए जगह है। इसका कार्य शीघ्र करवाया जाए।	तकनीकी शिक्षा
23.	निर्वाचन क्षेत्र में सड़के बनी हुई हैं लेकिन बसें नहीं हैं। बसें उपलब्ध करवाई जाएं।	HRTC

11. जिला ऊना

1. श्री राकेश कालिया, गगरेट

1.	स्वां नदी के चैनलाईजेशन प्रोजेक्ट का आधा काम रुक गया है इसके लिए पैसा सैंक्शन है लेकिन रिलीज नहीं हुआ है। भारत सरकार से बजट का प्रावधान शीघ्र करवाया जाए ताकि प्रोजेक्ट का रुका हुआ शेष कार्य भी जल्द हो सके।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
----	---	-------------------------------

2.	गगरेट कॉलेज में जो लैक्चरर और प्रोफ़ेसर कार्यरत थे उन्हें सरप्लस होने के कारण निकाला गया था, उन्हें वहीं रखा जाए।	शिक्षा विभाग
3.	गगरेट में तहसील सैंक्शन हो गई है वहां तहसीलदार और अन्य स्टाफ को भी जल्दी भरा जाए।	राजस्व विभाग
4.	पंजाब में बन्दर और नीलगाय की समस्या के समाधान के लिए 70:30 के ratio में सरकार फैंसिंग के लिए subsidy दे रही है। इसके लिए हिमाचल सरकार भी कंटीली तारें लगाने के लिए subsidy दें ताकि बन्दरों और नीलगायों से फसलों को होने वाली तबाही से बचाया जा सके।	वन्य प्राणी विभाग
5.	ब्यास की Tributaries के लिए सिंचाई प्रोजैक्ट तैयार किया गया है। भारत सरकार से इसके लिए धन का प्रावधान करवाया जाए। निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा खड्डें हैं और खड्डों से जो जमीन reclaim हो रही हैं उसके लिए Flood Protection के अन्तर्गत स्वां reclaimed क्षेत्र के लिए डेढ़ सौ करोड़ रु० का सिंचाई प्रोजैक्ट का प्लान बनाया है। जितनी भी जमीन reclaim हुई है, उसे सिंचित करने के लिए धन का प्रावधान किया जाए इससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	नंगल-तलवाड़ा-मुबारकपुर सड़क पर मुबारकपुर से लेकर मरवाड़ी बैरियल तक का भाग बहुत खराब हो चुका है तथा दूसरी सड़क, इसपुर से दौलतपुर के estimate विभाग के पास हैं, इनकी मुरम्मत शीघ्र करवाई जाए।	लो०नि० विभाग
7.	निर्वाचन क्षेत्र गगरेट के अस्पताल में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग

12. जिला हमीरपुर

1. श्री ईश्वर दास धीमान, भोरंज

1.	विधायक प्राथमिकताओं की 18 स्कीमों में से तीन ही स्वीकृत हुई हैं। लो०नि०वि० के XEN व JEs के लगातार तबादले किए जा रहे हैं। Executing Officers को यदि तीन वर्ष से पहले न बदला जाए तो अधिक प्राथमिकताओं की स्वीकृति हो सकती है।	लो०नि० विभाग
2.	तीन वर्ष पहले सीर खड्ड के चैनेलाईजेशन के लिए 62 करोड़ स्वीकृत हुए हैं लेकिन इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। बरसात में सीर खड्ड से हो रहे भारी नुकसान के मद्देनजर इसके तटीयकरण का कार्य शीघ्र किया जाए जिससे किसानों की हजारों एकड़ भूमि को बचाया जा सके। बाढ़ / भारी वर्षा से हुए नुकसान से अभी तक राहत के तौर पर भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य / राजस्व विभाग/ उपायुक्त हमीरपुर

2. श्री नरेन्द्र ठाकुर, सुजानपुर		
1.	पिछले वर्ष की विधायक प्राथमिकता योजनाओं की कुछ सड़कों की डीपीआर, जिनमें कोई भी झगड़ा नहीं है, अभी तक नहीं बन पाई है। लिंक रोड आंसला से सौड सड़क, मरहाणा, भराड़ा से घसोली, घराडू से हरोली सड़कों की डीपीआर शीघ्र तैयार की जाए।	लो0नि0 विभाग
2.	सुजानपुर में मिनी सचिवालय का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।	सामान्य प्रशासन/DC
3.	सुजानपुर में बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए। फरीदाबाद-कक्कड बस वाया मैहसक्वार चलाई जाए।	HRTC/बस अड्डा प्राधिकरण
4.	सुजानपुर में खेती-बाड़ी व कृषि का कार्य बन्दरों, जंगली तथा आवारा पशुओं की वजह से लगभग खत्म ही हो गया है। इनको रोकने के लिए Drastic action शीघ्र लिया जाए।	वन्य प्राणी/ कृषि/पशुपालन विभाग
5.	लो0नि0वि0 ने खैर से नालम्बर स्कीम तथा रंगर से सनु खड्ड की जैसे ही डीपीआर तैयार करके नाबार्ड को भेजी है, विभाग द्वारा वहां भूमि पूजन करवा दिया गया जबकि इस स्कीम की स्वीकृति अभी तक नहीं आई है।	लो0नि0 विभाग
2. श्री इन्द्रदत्त लखनपाल, बड़सर		
1.	बिजड़ी में तहसील कार्यालय के भवन का काम आधा रुका है जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाए।	लो0नि0/ राजस्व विभाग
2.	तीन स्कूलों के साईंस ब्लॉक का कार्य प्रगति पर है लेकिन कुछ समय से धन न होने के कारण काम रुका पड़ा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जारली, टिप्पर तथा ब्यारा के भवन के निर्माण के लिए 50-50 लाख अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान शीघ्र किया जाए।	शिक्षा विभाग
3.	राजकीय महाविधालय बड़सर के ग्राउंड का आधा काम हुआ है तथा एक भवन जो बनने को है, उसके लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग
4.	बड़सर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कों की स्थिति बहुत खराब है इसके लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाए।	लो0नि0 विभाग
5.	आई0पी0एच0 तथा लो0नि0वि0 में दो-दो जे0ई0 तथा दो एस0डी0ओ0 के पद खाली हैं व भोरंज डिवीजन में एस0डी0ओ0 नहीं है। स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
6.	बड़सर निर्वाचन क्षेत्र में बसों के कई रूट बंद पड़े हैं। राईपुर-शिमला बस काफी समय से बंद है तथा ऐसे ही लोकल बसों के भी चार-पांच रूट बंद हैं, इन्हे शीघ्र शुरू किया जाए।	HRTC

7.	आई0पी0एच0 की वॉटर सप्लाई की स्कीमें ठेके पर दी जा रही हैं। ठेकेदारों ने अकुशल वर्कर रखे हैं। हर तीसरे दिन मोटर जल जाती है तथा भारी-भरकम पैसा मोटरों की रिपेयर पर खर्च हो रहा है। अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को सही तरीके से पानी मिले।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
8.	बिजली विभाग में बड़सर डीविजन में एक स्टोर था जिसे हमीरपुर शिफ्ट किया गया है, इसे restore किया जाए।	HPSEBL

दो दिवसीय बैठकों के अन्त में मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि दो दिनों की बैठकों में 68 विधायकों में से 48 माननीय विधायकों ने भाग लिया। बैठकों में प्रदेश महत्व के विभिन्न मुद्दे माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए हैं। कुछ मुद्दों पर बैठकों में ही निर्णय लिए गए हैं। अन्य मुद्दों पर विभाग तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत करवाएंगे। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा तथा विकास में रही चुटियों को दूर किया जाएगा।

बैठकों के समापन पर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया कि दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा तुरन्त एवं पूर्णतः से पालन किया जाएगा। प्रदेश के चहूंमुखी तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के लिए सम्पूर्ण प्रशासन सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा। सभी सम्बन्धित विभाग बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे। दो दिवसीय बैठकों धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई।

दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश

क्र० सं०	माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश	सम्बन्धित विभाग
1.	विभाग योजनाओं की लम्बित DPR चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं की स्वीकृति समय पर प्राप्त की जा सके। आवश्यकतानुसार DPR तैयार करने का कार्य, outsource किया जाए। FCA Clearances के मामले DPR तैयार करने से पहले तैयार करें। FCA Clearances के कार्य को एक अभियान के रूप में पूर्ण करने के प्रयास किए जाएं। सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा किया जाए ताकि अनावश्यक लागत वृद्धि से बचा जा सके। सड़कों की लम्बित DPR को शीघ्र स्वीकृति/निपटाने के लिए लो०नि०वि०, वन व राजस्व तीनों विभागों के अधिकारियों की नियमित संयुक्त बैठक की जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/लोक निर्माण/वन विभाग
2.	मुख्यमंत्री द्वारा की गई लम्बित घोषणाओं को शीघ्र implement किया जाए।	लोक निर्माण/सिं. एवं ज. स्वा. एवं सभी सम्बन्धित विभाग
3.	डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए जहां सरपल्स डाक्टर हैं उन्हें आवश्यकता वाली जगह पर तैनात किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	दूरदराज क्षेत्रों में जो डाक्टर तैनात किये जाते हैं उनके cancellation orders न किए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
5.	पच्छद निर्वाचन क्षेत्र में जे०ई० के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं।	लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
6.	पच्छद निर्वाचन क्षेत्र में जहां हैंडपम्प लगने है वहां हैंडपम्प लगाए जाएं ताकि पीने के पानी की कमी न आए। हैंडपम्पों की लम्बित डी०पी०आर० शीघ्र बनाई जाएं।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
7.	पच्छद निर्वाचन क्षेत्र के सरांह में एस०डी०एम० कार्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा।	सामान्य प्रशासन
8.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित पुरानी स्कीमों का रख-रखाव किया जाए। जो पम्प obsolete हो गए हैं, उन्हें बदला जाए। जो मुरम्मत योग्य पाईपें और पम्प हैं उनकी मुरम्मत करवाई जाए ताकि पेयजल/सिंचाई स्कीमें सुचारु रूप से कार्य करें।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
9.	तीन-तीन, चार-चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बन्दरों की नसबन्दी का एक केन्द्र खोले जाने बारे विचार किया जाए।	वन्य प्राणी/पशुपालन विभाग
10.	शिलाई क्षेत्र के वन भूमि में हो रहे अवैध खनन को रोका जाए।	वन/खनन विभाग
11.	नेरवा अस्पताल के भवन निर्माण के लिए टेंडर शीघ्र लगाया जाए।	स्वास्थ्य/लो०नि० विभाग

12.	वन विभाग कुपवी-दईया सड़क के आगे वाले शेष भाग का फॉरेस्ट क्लीयरेंस केस शीघ्र भेजे।	वन/ लो0नि0 विभाग
13.	सैंज-फेड़ज पुल सड़क को कम से कम चौपाल तक किसी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चौड़ा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
14.	चौपाल चुनाव क्षेत्र के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरांह के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाए व इस भवन का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए।	शिक्षा विभाग
15.	भटठाकुफर स्कूल की सीवरेज लाईन को मेन सीवरेज लाईन में जोड़ा जाए।	शिक्षा/न.निगम शिमला/ शहरी विकास विभाग
16.	RKMV IInd चरण के कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	शिक्षा/ लो0 नि0 विभाग
17.	लो0नि0वि0 के उपमण्डल रोहडू के डोडरा-क्वार में XEN की नियुक्ति शीघ्र की जाये।	लो0 नि0 विभाग
18.	परिवहन निगम ग्रामीण इलाकों की सड़कों को ध्यान में रखते हुए छोटी बसें उपलब्ध करवाये।	परिवहन निगम
19.	सड़कों और पब्लिक बिल्डिंग्स की मुरम्मत/रख-रखाव के लिए विधायक निधि से भी पैसा दिया जाए।	योजना विभाग (R&DP Div)
20.	जो ठेकेदार टेंडर अवार्ड होने पर कार्य को सरेन्डर कर देते हैं, जिस कारण परियोजनाओं के निर्माण में देरी हो जाती है, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ विभाग कार्यवाही करें।	लो0नि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
21.	छूटी हुई आबादियों में बड़ी स्कीमें बनाने की जगह छोटी-2 स्कीमें बनाई जाएं ताकि लोगों को निर्मित स्कीमों का शीघ्र लाभ मिल सके।	लो0 नि0/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ समस्त उपायुक्त
22.	लाहौल-स्पीति में आयुर्वेद विभाग के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाए।	आयुर्वेद विभाग
23.	लाहौल-स्पीति भवन मनाली को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से वापिस लेकर उपायुक्त लाहौल-स्पीति को सौंपा जाए।	उपायुक्त लाहौल
24.	जिन सड़कों की टारिंग उखड़ गई है, उन सड़कों की पुनः टारिंग की जाए। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए व लो0नि0वि0 का inspection wing निर्माणाधीन सड़कों की जांच करे व दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।	लो0 नि0 विभाग
25.	एक ठेकेदार को उतने ही कार्य दिये जाने चाहिए जिनका वह ठीक से कार्य कर सके।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
26.	प्रदेश में आवश्यकतानुसार विभिन्न सरकारी संस्थान खोले एवं अपग्रेड किए गए हैं। जिन संस्थानों में स्टाफ की कमी है वहाँ पर आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र की जाए।	समस्त विभाग
27.	फील्ड स्टाफ जैसे कि पम्प ऑपरेटर, सर्वेयर, कनिष्ठ अभियन्ता	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/

	लाईनमैन, पटवारी, इत्यादि के खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए । दूर दराज के क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए ।	लो0नि0/ स्वास्थ्य/ शिक्षा/ समस्त सम्बन्धित विभाग
28.	प्रदेश के ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में बिजली की निर्विघ्न आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें। बिजली के खम्बों एवं Transformers की आपूर्ति आवश्यकतानुसार की जाए।	विद्युत विभाग / HPSEBL
29.	कॉलेजों, अन्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थाओं एवं Upgraded संस्थानों के लिए भवनों की व्यवस्था की जाए।	प्रारम्भिक/ उच्च शिक्षा स्वास्थ्य/ आयुर्वेद विभाग
30.	दिल्ली से पांवटा बॉल्चो बस का ट्रायल बंद न किया जाये। ट्रायल कम से कम छः महीने तक चलायें।	परिवहन निगम/ HRTC
31.	रैफरल अस्पताल बिलासपुर के लिए generator लगाने को 37 लाख रु0 का प्रावधान किया गया था, जोकि लो0नि0वि0 के electrical division Una के पास पड़े हैं, इस बारे जांच की जाए।	स्वास्थ्य/ लो0नि0 विभाग
32.	विधायकों की प्राथमिकताओं की पुरानी सिंचाई स्कीमों एवं हैण्डपम्पों का उचित रखरखाव किया जाए।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
33.	लोगों द्वारा Proper Septic Tank बनाए जाएं। लोगों को Proper Sewerage Connectivity उपलब्ध करवाई जाये।	शहरी विकास विभाग/नगर निगम शिमला
34.	पिछड़े घोषित एवं जन जातीय क्षेत्रों से स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी को तभी Relieve किया जाना चाहिए जब Reliever join कर ले।	जनजातीय विकास एवं अन्य समस्त सम्बन्धित विभाग

वार्षिक बजट (2016-17) के लिए विधायक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 2016 को होने वाली बैठकों के लिए श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मन्त्री, का उद्घाटन भाषण ।

- मैं, समस्त प्रतिभागियों का वर्ष 2016-17 के बजट के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु आयोजित इस बैठक में स्वागत करता हूँ ।
- प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सफल एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मैं प्रदेश की जनता, सभी विधायकों एवं प्रशासन को बधाई देता हूँ।
- इन बैठकों में प्राप्त सुझाव, प्रदेश की आगामी वर्ष के लिए विकास नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होंगे । हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के संतुलित विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। हम “सर्व कल्याण समग्र विकास” के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं ।
- प्रदेश की जनता को स्वच्छ शासन, कुशल प्रशासन, जबावदेह एवं पारदर्शी सरकार प्रदान करना हमारा उद्देश्य है ।
- प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी नीति निर्देशक दस्तावेज माना है । कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के लगभग सभी वायदे पूरे किए जा चुके हैं ।
- उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल में बढ़ोतरी करने के उपायों पर कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके ।
- प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास निगम का गठन किया जा चुका है । एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदेश में कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 640 करोड़ रुपये की परियोजना को सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । प्रदेश में पांच वर्षों में 86,000 बेरोजगारों को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण

प्रदान करने का लक्ष्य है । साथ ही प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी ।

- वर्ष 2015-16 के लिए राज्य योजना का आकार 4,800 करोड़ रुपये है। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य योजना आकार 5,200 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- डी0पी0आर0 तैयार करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए सरकार ने डी0पी0आर0 को **outsource** करके तैयार करने के लिए चालू वर्ष के बजट में धनराशि उपलब्ध करवाई है ताकि डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार की जा सकें ।
- मैंने लोक निर्माण और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की **DPRs** सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त शीघ्र तैयार की जाएं ।
- **FCA** के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए वन, राजस्व तथा सम्बन्धित विभागों को **Joint Inspection** करने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।
- खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कृषि कर्मण्य पुरस्कार 2014-15 के लिए चयनित किया है । पुरस्कार में कृषि मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि, Trophy और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मैं इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों तथा कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ ।
- प्रदेश सरकार के निरन्तर प्रयासों के पश्चात, केन्द्र सरकार ने **core** केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण की हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश के लिए 90:10 के अनुपात में जारी रखने का निर्णय लिया है । मैं समस्त प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देता हूँ कि इस निर्णय का लाभ उठाने के उद्देश्य से माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वप्रथम भारत सरकार की **grant based** कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्त पोषित करने के प्रयास किए जाएं ।
- प्रदेश के विकास में नाबार्ड से प्राप्त ऋण सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न विधायक प्राथमिकताओं के लिए 584 करोड़ रुपये की नाबार्ड ऋण सहायता आज तक स्वीकृत हो चुकी है ।

- मेरा विभागों से आग्रह है कि स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य निश्चित समय अवधि में पूर्ण किए जाएं ताकि अतिरिक्त समय एवं लागत वृद्धि से बचा जा सके और योजनाओं का लाभ भी स्थानीय जनता को समय पर प्राप्त हो सके ।
- सभी विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र की विधायक प्राथमिकता की योजनाओं का **Status** उपलब्ध करवाया गया है । मैं, सभी माननीय विधायकों से आग्रह करता हूँ कि यदि **Status** में कोई त्रुटि हो तो उसे योजना विभाग के ध्यान में लाएं ताकि इसे ठीक किया जा सके ।
- मैं माननीय विधायकों के अनुरोध पर सरकार द्वारा प्रति विधान सभा डी०पी०आर० नार्ड को भेजने की अधिकतम सीमा जो 2014-15 से 2017-18 के लिए 50 करोड़ रुपये है, को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ ।
- आपसे यह भी अनुरोध है कि आप यदि अपनी विकास योजनाओं की सूचना को बैठक में उपलब्ध न करवा सकें तो शीघ्र योजना विभाग को भिजवा दें ताकि आपकी योजनाओं को अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जा सके ।
- माननीय विधायकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्राथमिकताओं के साथ प्रदेश के आगामी बजट के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दें ।
- मैं इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूँ कि बारी-बारी से माननीय मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव एवं विधायकगण अपने विचार इस बैठक में रखें ।

जय हिन्द ।

माननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की जिलावार समय सारणी

क्र० सं०	जिले का नाम	दिनांक	समय
1.	1. सोलन 2. सिरमौर 3. शिमला	04-02-2016	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
2.	1. मण्डी 2. कुल्लू 3. बिलासपुर	04-02-2016	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे
3.	1. कांगड़ा 3. लाहौल व स्पीति 3. किन्नौर	05-02-2016	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
4.	1. चम्बा 2. ऊना 3. हमीरपुर	05-02-2016	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे

माननीय मुख्य मन्त्री, हि०प्र०, की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की दो दिवसीय बैठकों में जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार भाग लेने वाले माननीय मन्त्री / मुख्य संसदीय सचिवों एवं विधायकों का ब्यौरा ।

(श्री गंगू राम मुसाफिर, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि०प्र०, दोनों दिन बैठकों में उपस्थित रहे)

क्र० सं०	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
04-02-2016 (प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक)				
1.	सोलन	1. अर्की	श्री गोबिन्द राम शर्मा	माननीय विधायक
		2. सोलन	डॉ० राजीव सैजल	माननीय विधायक
		3. कसौली	श्री धनी राम शॉडिल	Hon'ble Min. (SJ & Emp.)
2.	सिरमौर	1. पच्छाद	श्री सुरेश कुमार	माननीय विधायक
		2. नाहन	डॉ० राजीव बिन्दल	माननीय विधायक
		3. श्री रेणुका जी	श्री विनय कुमार	Hon'ble CPS, PWD
		4. शिलाई	श्री बलदेव सिंह तोमर	माननीय विधायक
3.	शिमला	1. चौपाल	श्री बलबीर सिंह वर्मा	माननीय विधायक
		2. कसुम्पटी	श्री अनिरुद्ध सिंह	माननीय विधायक
		3. शिमला	श्री सुरेश भारद्वाज	माननीय विधायक
		4. शिमला ग्रामीण	श्री वीरभद्र सिंह	Hon'ble Chief Minister, HP
		5. जुब्बल-कोटखर्बाई	श्री रोहित ठाकुर	Hon'ble CPS, Agri.
		6. रामपुर	श्री नन्द लाल	Hon'ble CPS, Health
		7. रोहडू	श्री मोहन लाल बराकटा	माननीय विधायक

04-02-2016 (सांय 2.00 बजे से 5.00 बजे तक)

4.	मण्डी	1. करसोग	श्री मन्शा राम	Hon'ble CPS, Trsm.
		2. सुन्दर नगर	श्री सोहन लाल	Hon'ble CPS, RD & PR
		3. सेराज	श्री जय राम ठाकुर	माननीय विधायक
		4. द्रंग	श्री कौल सिंह ठाकुर	Hon'ble Min. (Health & F.Wel., Rev. and Law.)
		5. धर्मपुर	श्री महेन्द्र सिंह	माननीय विधायक
		6. मण्डी	श्री अनिल कुमार	Hon'ble Min. (RD, PR & AH)
		7. बल्ह	श्री प्रकाश चौधरी	Hon'ble Min. (Excise & Taxation and (P&S)
		8. सरकाघाट	श्री इन्द्र सिंह	माननीय विधायक
5.	कुल्लू	1. मनाली	श्री गोविन्द राम ठाकुर	माननीय विधायक
		2. बन्जार	श्री कर्ण सिंह	Hon'ble Minister
		3. आनी	श्री खूब राम	माननीय विधायक
6.	बिलासपुर	1. घुमारवीं	श्री राजेश धर्माणी	Hon'ble CPS, Forest
		2. बिलासपुर	श्री बम्बर ठाकुर	माननीय विधायक
		3. श्री नैनादेवीजी	श्री रणधीर शर्मा	माननीय विधायक

क्र० सं०	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
05-02-2016 (प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक)				
7.	कांगड़ा	1. इन्दौरा	श्री मनोहर धीमान	माननीय विधायक
		2. फतेहपुर	श्री सुजान सिंह पठनियां	Hon'ble Min. (MPP & Power and NES)
		3. ज्वाली	श्री नीरज भारती	Hon'ble CPS (Edu.)
		4. ज्वालामुखी	श्री संजय रतन	माननीय विधायक
		5. जयसिंहपुर	श्री यादविन्द्र सिंह गोमा	माननीय विधायक
		6. सुलह	श्री जगजीवन पॉल	Hon'ble CPS (IPH)
		7. नगरोटा	श्री जी०एस० बाली	Hon'ble Min. (Food, Civil Supp. & Con., Tpt, Tech. Edu.)
		8. धर्मशाला	श्री सुधीर शर्मा	Hon'ble Minister (UD) Housing & TCP
		9. बैजनाथ	श्री किशोरी लाल	माननीय विधायक
8.	लाहौल-स्पीति	1. लाहौल-स्पीति	श्री रवि ठाकुर	माननीय विधायक
9.	किन्नौर	1. किन्नौर	श्री जगत सिंह नेगी	Hon'ble Dy.Speaker, HPVS
05-02-2016 (सांय 2.00 बजे से 5.00 बजे तक)				
10.	चम्बा	1. चुराह	श्री हंस राज	माननीय विधायक
		2. भरमौर	श्री ठाकुर सिंह भरमौरी	Hon'ble Min. (Forest and Fisheries)
		3. डलहौजी	श्रीमती आशा कुमारी	माननीय विधायक
		4. भटियात	श्री विक्रम सिंह जरयाल	माननीय विधायक
11.	ऊना	1. गगरेट	श्री राकेश कालिया	माननीय विधायक
		2. हरोली	श्री मुकेश अग्निहोत्री	Hon'ble Min. (Ind.) Labour & Emp., Parliamentary Affairs, Inf. & Pub. Relations.
12.	हमीरपुर	1. भोरंज	श्री ईश्वर दास धीमान	माननीय विधायक
		2. सुजानपुर	श्री नरेन्द्र ठाकुर	माननीय विधायक
		3. बड़सर	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	Hon'ble CPS (RD & PR)
